

## Foreword

The Monsoon session of the parliament for the year 2011 started in the context of the nation seeking solution from Congress led UPA government on various important issues. Bharatiya Janata Party as the main opposition party in the parliament tried to bring the concern of the people into the focus of the debate. The issue of corruption, rising prices, terrorism, national security and criminal inaction of the government on a range of the issues including demand of Telangana were brought to the fore. The lack of transparency and accountability has crippled the governance resulting in multiple centres of power affecting the functioning of the government. As the government remains adamant in crushing all voices of opposition, the democratic culture of the country appears to have suffered heavily in the face of government repression and police action. The sufferings of the people have led them to oppose the government on a massive scale and the government seems to have lost all moral right to continue in power.

The BJP leaders have raised several issues in the parliament. Leader of Opposition in Lok Sabha Smt. Sushma Swaraj speaking on Calling Attention motion took the government to task for its dilly dallying approach on the creation of Telangana State. Leader of Opposition in Rajya Sabha Shri Arun Jaitley has highlighted the failure of the Congress led UPA government in checking the tide of terrorism and for having failed in taking strong measures on the issue of national security. Shri Yashwant Sinha effectively raised the voice of common people by speaking on the issue of price rise. In Rajya Sabha BJP National General Secretary and National Spokesperson Shri Ravishankar Prasad also exposed the failure of the government on the issue of terrorism and national security. Leader of Opposition in Rajya Sabha Shri Arun Jaitley and in Lok Sabha Shri Yashwant Sinha spoke on CWG scam. We are publishing all the speeches for our esteemed readers.

**Publisher**  
**Bharatiya Janata Party**  
**11, Ashok Road,**  
**New Delhi - 110 001**

**August, 2011**

**Monsoon Session 2011**

## **BJP in Parliament**



- ◆ **Sushma Swaraj**
- ◆ **Arun Jaitley**
- ◆ **Yashwant Sinha**
- ◆ **Ravishankar Prasad**



**BHARATIYA JANATA PARTY**

## तेलंगाना मुद्दे पर कांग्रेस ने की वादाखिलाफी : सुषमा स्वराज

तेलंगाना राज्य गठन के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की वादाखिलाफी पर जमकर प्रहार किया। श्रीमती स्वराज ने तेलंगाना राज्य गठन के बारे में सरकार से विधेयक लाने का आग्रह कर आश्वासन दिया कि भाजपा इस विधेयक को दो तिहाई बहुमत दिलाने में पूर्ण सहयोग करेगी। हम यहां श्रीमती स्वराज द्वारा दिए गए भाषण का संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:—

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत लोक महत्व के विषय की तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

“तेलंगाना राज्य के गठन में हुए विलंब से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम”

अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से 17 एमपीज इस सदन में जीतकर आते हैं, लेकिन 13 एमपीज ने अपनी पीड़ा और आक्रोश को अभिव्यक्ति देते हुए इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

आंध्र प्रदेश की विधान सभा में 119 लोग तेलंगाना रीजन से जीतकर आते हैं और 101 लोगों ने आंध्र प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अभी आपके सामने एक साथी उधर से बोल रहे थे कि तेलंगाना के विषय में चर्चा होनी चाहिए।

इन्होंने जिन तीनों के नाम लिए हैं, उन तीनों और एक अन्य यानी चार

सदस्यों ने रिजाइन नहीं किया और 13 ने रिजाइन किया है। जिन तीनों के नाम हैं, यह सच है कि इन तीनों ने रिजाइन नहीं किया। जिन चार लोगों ने रिजाइन नहीं किया, इन्होंने उनके नाम लिए हैं कि श्री जयपाल रेड्डी ने रिजाइन नहीं किया और बाकी दो ने रिजाइन नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए कह रही थी कि देश की लोक सभा और आंध्र प्रदेश की विधान सभा में धीरे-धीरे बेजुबान हो रहे तेलंगाना को जुबान देने के लिए मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष जी, तेलंगाना का इतिहास एक तरफ संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विश्वासघात के प्रसंगों से भी पटा पड़ा है। पता नहीं इस सदन में कितने लोगों को यह मालूम है कि भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ, लेकिन तेलंगाना उसके साथ आजाद नहीं हुआ। तेलंगाना 17 सितम्बर, 1948 को आजाद हुआ, यानी भारत की आजादी के भी एक वर्ष से ज्यादा संघर्ष करके, हजारों लोगों के बलिदान के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। अभी वे आजादी की पूरी खुशी मना भी नहीं पा रहे थे कि उनके सिर पर आंध्र प्रदेश के साथ विलय की तलवार लटक गयी। वे लोग आंध्र प्रदेश के साथ विलय नहीं चाहते थे, इसलिए विरोध शुरू हुआ। वर्ष 1953 में एक फजल अली कमीशन बैठा। उन्होंने कहा कि यह विलय उचित नहीं होगा और अगर विलय करना ही है, तो वर्ष 1961 का एक चुनाव हो जाने दो। वहां तेलंगाना के रीजन से आये हुए अगर दो—तिहाई विधायक यह कहें कि आंध्र प्रदेश में विलय कर दो, तब करना वरना मत करना।

अध्यक्ष महोदया, मैं उधर बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत पापुलर प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस विलय को बेमेल बताते हुए यह कहा था कि आंध्र और तेलंगाना का विलय उसी तरह से है जिस तरह से एक इनोसेंट लड़की, एक भोली-भाली लड़की की शादी एक मिसचीवियस बॉय, एक शरारती लड़के से कर दी जाये। उन्होंने यह कहा था कि यह शादी नहीं चलेगी। जब यह शादी न चले, तो यह पति-पत्नी की तरह अलग-अलग हो जायें।

अध्यक्ष जी, मैं किसी भाजपाई नेता को कोट नहीं कर रही। यह पंडित जी का बहुचर्चित कोट है, जो उस समय के अखबारों में छपा था। मैं इन्हें कहना चाहती हूँ कि 6 मार्च, 1956 का इंडियन एक्सप्रेस निकाल कर देख लें, इनवर्टेड कोमाज में यह कोट छपा हुआ है। अध्यक्ष जी, तेलंगाना के

लोगों के विरोध के बावजूद यह विलय हो गया।

अध्यक्ष जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद विलय हो गया। विलय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये। तरह-तरह के फार्मूले अपनाए जैसे मुल्की रूल्स, प्रेजिडेंशियल आर्डर्स, फार्मूला नम्बर सिक्स, जीओ नम्बर 610, गिगलानी कमीशन बना। इतने उपाय किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि सारे उपाय कागजों में रह गए, धरती पर नहीं उतर पाए। इस सबका नतीजा वही हुआ—मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। यह पुराना इतिहास इसलिए बताया क्योंकि मैंने पहले कहा था कि तेलंगाना के निर्माण में देरी हो रही है, शायद गृहमंत्री जी इरीटेट हो रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती थी। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं ले रही हूँ। यह इतिहास बताना जरूरी था ताकि सदन को यह समझ में आ जाए कि विलय की पृष्ठभूमि क्या है।

अब मैं वर्तमान पर आ रही हूँ और वर्तमान शुरू करूंगी वर्ष 2004 से, यूपीए की पहली सरकार से। वर्ष 2004 में कांग्रेस का टीआरएस के साथ समझौता हुआ, इकट्ठे चुनाव मैदान में गए। उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष ने करीम नगर की एक सभा में लोगों को आश्वासन दिया कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। लोगों ने विश्वास किया और झोली भर-भरकर इनको वोट दिए। उसके बाद ये सरकार में आ गए, सरकार में टीआरएस इनका एक पार्टनर था। पार्टनर बनने के बाद इन्होंने एक सीएमपी बनाया। अभी कोई भी यहां बैठे नहीं हैं।

एक सीएमपी बना। उस सीएमपी में इन्होंने तीन राइडर्स के साथ तेलंगाना की डिमाण्ड के बारे में लिखा :

"The UPA Government will consider the demand for the formation of the State at an appropriate time after due consultations and consensus."

तीन राइडर्स इन्होंने लगाए। यह मई, 2004 का सीएमपी है जब सरकार बनी। उसके बाद जून में पहला राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ। उसी सीएमपी से भाषा उठाई गयी, मगर एक राइडर हटा दिया गया। मैं राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूँ :

"The Government will consider the demand for the formation of a State at an appropriate time and after due consultations."

इसमें कंसेन्सस शब्द हट गया। हमें लगा इवोल्यूशन हुआ है, तीन

राइडर्स थे सीएमपी में, लेकिन शायद सरकार वाकई गंभीर है और वे कंसेन्सस की बात करके रूक गए क्योंकि शायद कंसेन्सस होना संभव नहीं था, तो कंसेन्सस शब्द हटा दिया गया। यह राष्ट्रपति का अभिभाषण है जो सरकार का नीति निर्देशक सिद्धान्त होता है, जिसको मानना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसको तो आप मानेंगे? सीएमपी के आधार पर राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ और उन्होंने एक राइडर हटाकर दो राइडर कर दिए। वर्ष 2004 से 2009 तक, पूरा कार्यकाल निकल गया, लेकिन वह उचित समय नहीं आया। कंसेन्सस हुई होंगी, बहुत राजनैतिक उठापटक हुई, टीआरएस से समझौता टूटा, उन्होंने रिजाइन किया, दुबारा चुनकर आए, फिर रिजाइन किया। उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वर्ष 2004 के बाद वर्ष 2009 का चुनाव हुआ, तेलंगाना के लोगों ने सोचा कि शायद हमें टीआरएस को ज्यादा जिता दिया था, इसलिए हमको तेलंगाना नहीं मिला, इस बार कांग्रेस को झोली भर-भर जिताओ, तो शायद हमें तेलंगाना मिल जाए। एक उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने वोट दिया और तेलंगाना से 17 में से 12 एमपी कांग्रेस के जीतकर आए जिनमें से एक सदस्य अभी यहां बैठे हैं।

हां, दो बैठे हैं, तभी मैंने कहा कि चार इधर बैठे हैं, 13 इस्तीफा देकर चले गए, इस्तीफा आपका भी है, मगर आप हाउस अटेंड कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप हाउस अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी जबान में जबान मिलाने वाला कोई एक स्वर तो है।

अध्यक्ष जी, वर्ष 2009 के चुनाव में 12 सांसद वहां से कांग्रेस के जीतकर आए, लेकिन छः महीने तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ा, तो 29 नवंबर, 2009 को टीआरएस के नेता के.एस. राव ने अनशन किया। यह विषय 7 नवंबर, 2009 को मैंने इस सदन में उठाया था। मैं आज पहली बार तेलंगाना पर नहीं बोल रही हूँ। तेलंगाना का निर्माण मेरा यह हमेशा प्रिय विषय रहा है क्योंकि हमारे यहां से वहां एक भी एमपी जीता नहीं है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नाते यह हमारा फर्ज बनता है। पहले नेता, प्रतिपक्ष के तौर पर आडवाणी जी हमेशा बोलते रहे और मैं बताउंगी कि आडवाणी जी ने क्या-क्या बोला? अब मैं नेता, प्रतिपक्ष के नाते मैं बोलती हूँ क्योंकि कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इतने बड़े विषय से अपने आपको अलग नहीं रख सकती है।

अध्यक्ष जी, 7 दिसम्बर को मैं बोली और वह विषय मैंने यहां उठाया। एक दिन के बाद यानी 9 दिसम्बर को आपने चेरर से इंटरवीन किया। के.

सी. राव जी की हालत बिगड़ रही थी। आपने चेयर से कहा कि पूरे का पूरा सदन उनके बारे में चिंतित है, कुछ होना चाहिए। उसके बाद सदन में हर पार्टी के नेता बोले। गुरुदास दासगुप्ता जी बैठे हैं, वह बोले, शरद यादव जी बोले, मुलायम सिंह जी बोले, लालू जी बोले, अनंत गीतेजी बोले, अजनाला जी बोले। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यहां न बोला हो। यह 9 दिसम्बर की बात है और 9 दिसम्बर बहुत अहम् है तेलंगाना के इतिहास की जिंदगी में इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूं। आप 9 दिसम्बर को बोलीं, आपके बाद सारे नेता बोले। फिर सरकार हरकत में आई। एक संयोग बना, 10 दिसम्बर को श्रीमती सोनिया गांधी का जन्म दिन होता है। 9 दिसम्बर की रात को, आज के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम ने, अर्धरात्रि को घोषणा की। वह घोषणा मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

The Home Minister Shri P. Chidambaram, late in the night said:

"The process of forming the State of will be initiated and appropriate Resolution will be moved in the Assembly. We are concerned about Rao's health. We request him to withdraw his fast immediately. We also appeal to all concerned specially students to withdraw their agitation and help restore normalcy."

सारे राइडर्स इसमें से हट गए। न कंसलेटेशंस, न कंसेंसस, एक कटेगोरिक एश्योरेंस गृहमंत्री जी की तरफ से आया और अर्धरात्रि को आया। उसी समय तेलंगाना में पटाखे फूटने लगे। वहां के लोगों को यह लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के जन्म दिन का तोहफा देश के गृहमंत्री ने उन्हें दिया है। आतिशबाजी हुई, रात को दीवाली हुई। पहली बार तेलंगाना के लोगों को यह उम्मीद पूरी होती लगी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने यह कहा – The process of forming the State of will be initiated and appropriate Resolution will be moved in the Assembly. इसमें कहीं कंसलेटेशंस और कंसेंसस की बात नहीं थी।

उन्हें लगा कि जन्मदिन का तोहफा मिला है। यह अच्छी बात थी। आप अच्छी बात को बुरा क्यों मानते हो। मैंने कहा कि इस पर खुश होकर लोगों ने पटाखे फोड़े।

मैंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने पटाखे फोड़े। उनकी उम्मीद विश्वास में बदल गई है, क्योंकि तारीख अहम् हो गई। आप अच्छी बात को भी बुरा मान रहे हैं।

आप मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दें, मैं थोड़ा सा इंडलर्जेस आपसे चाहती हूं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। अध्यक्ष जी, 10 दिसम्बर को जब सदन की बैठक शुरू हुई, तब नेता प्रतिपक्ष आडवाणी जी खड़े हुए। आडवाणी जी ने कहा कि "मैं बहुत आभारी हूं आप मुझे अवसर दे रही हैं। मैं सदन को इस बात के लिए बधाई दूँ कि आपने सदन में जिस प्रकार आंध्र प्रदेश की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई और संसद को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन दो बातों के बारे में सदन में कल चिंता प्रकट की गई थी। उन दोनों बातों का एक प्रकार के समाधान हो गया। हम चाहते थे कि तेलंगाना की जनता की इच्छा के अनुसार तेलंगाना प्रदेश बने। हम चाहते थे कि हमारी संसद के साथी जो दस दिन से अनशन पर थे, जिनके स्वास्थ्य की हालत चिंताजनक हो गई थी, उनके जीवन को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, ये दोनों बातें हो गईं, मुझे इसकी बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।"

अध्यक्ष जी, मैं यह बात केवल इसलिए कह रही हूँ कि केवल तेलंगाना में ही नहीं, बल्कि सदन की भी उम्मीद विश्वास में बदल गई। हमें लगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दस दिसम्बर को प्रणब मुखर्जी साहब भी यहां बोले थे और बधाई दी सदन में, क्योंकि हमें यह लगा कि नौ दिसम्बर का वह दिन माइलस्टोन बनेगा, मील का पत्थर बनेगा, तेलंगाना के निर्माण में।

लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे हैरानी है कि 9 दिसम्बर को इस सदन में यह सब घटता है, तेलंगाना में पटाखे चलते हैं। लेकिन 23 तारीख को गृहमंत्री जी बदल गये और 14 दिन के अंदर गृहमंत्री का बयान आ गया, there is no consensus on creation. मैं पूछना चाहती हूँ कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने कंसेंसस शब्द हटा दिया था, आपने कहा था केवल वाइडर कंसल्टेशन्स, नो कंसेंसस, आपने कोई बात कंसेंसस की नहीं की थी। 23 दिसम्बर को जबकि प्रोसेस इनीशिएट हो जाना चाहिए था आपने कंसेंसस की बात करके वापिस back to square one लाकर खड़ा कर दिया। 23 दिसम्बर को ये बदल गये और इस सारे में से निकला, जस्टिस श्रीकृष्णा कमीशन, जिसका जिक्र अभी अपनी रिपोर्ट में, अभी अपने वक्तव्य में गृहमंत्री जी ने किया है। मैं आज कहना चाहती हूँ, बिना संकोच के कहना चाहती हूँ कि जस्टिस श्रीकृष्णा कमीशन ने जितना इंजस्टिस तेलंगाना के साथ

किया है, उसे तेलंगाना का इतिहास कभी भूलेगा नहीं।

आप मुझे केवल पांच मिनट दें। माननीय गृहमंत्री जी का पूरा वक्तव्य श्रीकृष्णा कमेटी रिपोर्ट पर है और आपने कहा है कि उन्होंने 6 फार्मूले आपको दिये। लेकिन यह पहली बार हुआ है अध्यक्ष जी कि इतने कमीशन और कमेटियां इस देश में बनीं, हमेशा उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। लेकिन पहला कमीशन है जिसने सार्वजनिक रिपोर्ट अलग से दी है और एक गुप्त रिपोर्ट अलग दी है, एक सीक्रेट रिपोर्ट उन्होंने इन्हें अलग से दी है और वह सीक्रेट रिपोर्ट जिसका जिक्र गृहमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं किया। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई एक सीक्रेट रिपोर्ट श्रीकृष्णा कमीशन ने आपको दी है और अगर ये मना करें तो उसका जवाब भी मैं देती हूँ लेकिन ये मना कर नहीं सकते हैं। क्योंकि आज के युग में कोई चीज गुप्त रह नहीं सकती, खोजी पत्रकार सब कुछ निकाल लाते हैं। अब तो रिपोर्ट पहले लीक हो जाती हैं। कांग्रेस के ही एक पूर्व सांसद श्री एम. नारायण रेड्डी ने एक याचिका आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की। उन्होंने यह कहा कि हमें यह पता चला है कि कृष्णा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक सीक्रेट रिपोर्ट भी दी है और उस सीक्रेट रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, यह प्रार्थना उन्होंने की। जिस बैंच के सामने यह पीटिशन लगी, उस बैंच के लोगों ने सरकार से कहा कि अगर ऐसा कोई डॉक्युमेंट है तो आपको उसे हमारे पास लाना होगा। वह रिपोर्ट उन्होंने वहां दी। अध्यक्ष जी, मैं कहीं और से नहीं, मैं उस जजमेंट से पढ़ रही हूँ।

वह जजमेंट पब्लिक डोमेन में है। जजमेंट का ऑपरेशन स्टे हुआ है। मैं केवल यह कह रही हूँ। आप नहीं कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई। मैं इसलिए नहीं बैठूंगी, क्योंकि इसी से पोल खुलेगी, आप मेरी पूरी बात सुनिए।

महोदया, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगी। जज ने कहा –

"The Committee travelled beyond the Terms of Reference in its endeavour to persuade the Union of India not to accede to the demand for . It is demonstrated in a three-page supplementary note appending to the note representing Chapter 8."

उन्होंने माना कि एक चैप्टर नोट एक है। आप हैरान हो जाएंगी, वह नोट है पालिटिकल मैनेजमेंट करिए, मीडिया मैनेजमेंट करिए। मैं सदन को चौंकाने वाली चीजें कह रही हूँ। उस नोट में लिखा है –

"There is a need for ensuring unity among the leaders of the

Ruling Party in the State. There is also a need for providing strong and firm political leadership and placement of representatives of in key positions. This aspect was discussed with FM and HM in September 2010. Action also needs to be initiated for softening the TRS to the extent possible. "

"The Congress high command must sensitize its own MPs and MLAs and educate them about the wisdom for arriving at an acceptable and workable solution. With the Ruling Party and main Opposition Party being brought on the same page, these support mechanisms have a higher probability of becoming successful. "

वह नोट कहता है कि मीडिया मैनेज करिए। मीडिया मैनेजमेंट के लिए कहा है कि वहां इतने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, इतने प्रिंट के चैनल्स हैं। महोदया, जस्टिस रेड्डी कहते हैं –

"More disturbing is the suggestion given by the Committee to the Government."

More disturbing is the suggestion given by the Committee to the Government and it reads:

"The print media is hugely dependent on the Government for advertisement revenue and if carefully handled can be an effective tool to achieve this goal."

महोदया, यह रिपोर्ट है। यह जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, यह एआईसीसी की रिपोर्ट है और आज तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है।

मैं अभी ओथेंटीकेट करके रख देती। यह जजमेंट की कापी है। गृहमंत्री जी, मैंने ये बातें इसलिए रखीं, क्योंकि वहां तरह-तरह के धोखे हो रहे हैं। यह जो सरकार की हरकत है, इससे हताश हो कर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में 600 लोग मर गए। महोदया, आप मुझे बैठने के लिए कह रही हैं, मैं जो बात कहने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली में एक लड़का आया, जिसका नाम यादी रेड्डी था। वह इतना बड़ा तेलगु का नोट आत्महत्या करने से पहले लिख कर गया। मैं केवल चार लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूँ। उस लड़के ने दिल्ली में आत्महत्या की। उसने लिखा कि हैदराबाद ट्रेन चढ़ने से पहले बहुत सारे ख्यालों में कुछ सोचता हुआ यहां आ गया। मैं चाहता था कि माँ के हाथ का खाना खाकर और आशीर्वाद लेकर आऊं, लेकिन लगा कि कहीं पैर पीछे न हट जाएं,

इसलिए ऐसा नहीं किया। मैं अपना इलाका छोड़ कर जा रहा हूँ। मैंने कितने सपने देखे थे। मैं तेलंगाना छोड़ कर जा रहा हूँ। मन में पूरा दुख है। सच बोलना है, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहां कैसे आ गया। यहां आने के बाद मन में एक ही इच्छा है और कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैंने जो सोचा, वह करूंगा। तेलंगाना होने के लिए मैं भी भागीदार बनूंगा।

अध्यक्ष जी, मुझे लगता था कि यह जितना संजीदा विषय है, उतनी संजीदगी से मुझे बोलने दिया जाएगा लेकिन उतनी संजीदगी से मुझे बोलने नहीं दिया गया, टोकाटोकी की गई। इसलिए मैं गृहमंत्री जी, आपसे ज्यादा कुछ न पूछते हुए एक निवेदन करना चाहती हूँ कि यह कंसेंसस बहुत हो गई, अब आपने प्रैस रिजोल्यूशन की बात की है जिसको चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरूरत नहीं है। मेरा यह कहना है कि मुझे कुछ नहीं पूछना है। मुझे एक निवेदन करना है, आप तेलंगाना का बिल लेकर आइए, यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, दो-तिहाई सांसद आपको चाहिए, हम वो सांसद जुटाएंगे।

प्रणव दा, आपने कल यह अपील की थी कि हम जो बिल ला रहे हैं, उन बिलों पर विपक्ष आकर साथ दे। आज मैं अपील कर रही हूँ, आप बिल लाइए। हम सब साथ देंगे और तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे और सरकार से बिल लाने के लिए अपील कर रही हूँ तो मैं सदन से भी अपील कर रही हूँ कि हमें तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों से एक अपील करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वे मरें नहीं, बल्कि वे तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं केवल वहां के अपने बहन-भाइयों से एक अपील करना चाहती हूँ:-

"Sodhara, Sodharimanulaara, Telangana kosam balidaanam vaddhu. Telangana Choodadaaniki Brathakaali, Brathakaali" It means: "Brothers and sisters, do not sacrifice your lives for Telangana. You should live to see Telangana."



## Mumbai Blast & National Security

### Fight against terror is a battle India cannot afford to lose : Arun Jaitley

*The terror has once again attacked Mumbai on 13 July 2011. A serial bomb blast killing 22 people and injuring hundreds has sent a shock wave in the entire nation. India is shocked, anguished and in pain. The repeated terror attacks have yet again failed to see the Congress led UPA acting with urgency and sincerity. It has led to a situation wherein a sense of being ditched and cheated by its own government prevails among the people. It is really shocking to see that the even heart rending scenes of terror victims, blood soaked streets and mangled corpses have failed to move the government to act. The Leader of the Opposition in Rajya Sabha Shri Arun Jaitley while speaking in the house on "Mumbai blasts and national security" touched upon various dimensions of terrorism and took the government to task for its failure to act effectively and decisively. His speech on 4th August 2011 while giving a deep insight into the current situation, dwells at length on the manner in which the government should act and the serious lacunae which has hitherto impaired the government policy on terrorism and national security. We are publishing the synopsis of his speech for the benefit of our readers.*

**M**r. Deputy Chairman, Sir, we have been discussing, since yesterday, the issue of national security, particularly in the wake of the 13th July blasts at three places in Mumbai. Needless to say, the blasts and the actions accompanying them, have to be condemned and have been rightly condemned by every section of this House.

They are condemnable and also worrisome for this country. Our worries, Sir, also increase because three weeks after the blasts, it appears that we do not have serious clues as to who the real culprits are. This attack on Mumbai is actually in a series of attacks where Mumbai has been repeatedly attacked. It started in

1993 with a serial blast in Mumbai. Then you have several important isolated cases which caused extensive damage. Then you had the train blasts. And then was the major 26/11 blast, the attack through the sea route. The 26/11 attack through the sea route, clearly from across the border, after the 9/11, perhaps, has been one of the most major terrorist strikes anywhere in the world. Now you have the 13th July attack where three crowded areas in Mumbai were picked up and bombs were planted in a structured manner in those areas. One of the questions which arises is: Why is Mumbai, repeatedly, chosen for such attacks? I have been closely following the statements of the Home Minister. He has carefully avoided answering the questions saying, "I know the answer; I have a hunch, but I do not want to really specify the reasons". I don't think, Sir, the reasons are a matter of great research being required or they are any closely guarded secret. The attack on Mumbai which comes in this entire chain, increases the credibility and visibility of the terrorist outfit which organizes all attacks. That is why Mumbai is repeatedly chosen.

The cities like Mumbai and Delhi, when they are chosen for attack by the outfits, their own visibility, their on credibility as a terrorist organization also gets noticed all over the world. Secondly, Sir, when these attacks are successful and not prevented, attacks on a place like Mumbai end up resulting in exposing the weakness of our security system. If these people can enter with ammunition, go to a number of places, plant them and then escape, how many people would be involved in organizing this? Those who manufacture these bombs, those who purchase ammonium nitrate and other such chemicals, those who provide the logistical support, transportation, escape, money and, maybe, finally even legal defence, are all involved in this. It always puzzles me that this exposes the weakness of our security system when terrorists infiltrate into the city and successfully organize these blasts.

I beg to differ with the Home Minister when he said, on the morning of 14th at Mumbai, that it was not an intelligence failure. The fact that so many people were involved, the fact that they successfully organized these blasts and managed to escape, the

fact the intelligence agencies did not know any of these things, that they had not infiltrated into these modules, is, itself, an intelligence failure. That the intelligence not knowing any of these things, when so many people must have been involved in this whole conspiracy to commit these ghastly crimes, is an intelligence failure. I think he understands intelligence failure as meaning that the intelligence had not informed and, therefore, nobody had an opportunity to act on the basis of the intelligence information. There is a fundamental difference between the two. The difference being that if the executing agency, normally, the police in Maharashtra, did not have the intelligence information, then, that is a separate issue. If intelligence information had been given and the Mumbai police had not acted, then, that would be a failure of the executing agency. There is a difference when the intelligence agency does not inform you that so many people in these modules are acting in this manner, that they have entered, and a likely warning is given, then, we admit that it is an intelligence failure. The third reason, I come back, why Mumbai is repeatedly chosen is because it is a commercial capital centre of India. And when India's commercial centre is attacked, then, obviously, it catches the global attention. And, fourthly, -- I say this with a sense of regret - on an issue where all of us should really be speaking the same language in the national interest, Mumbai is chosen also for reasons that once Mumbai is attacked and people are identified, irrespective of those who are there, you always find people, keeping the character of the city in mind, who will come up and say, "People have been wrongly harassed and, therefore, let us now go soft on this." I shall, in the course of my intervention, try to highlight this point as well. Mumbai having been repeatedly attacked, after the attack, now, a debate starts in this country about the spirit of Mumbai. I am, at times, puzzled that these days on public issues, rather than political thinkers and political leaders, as our colleagues just now rightly mentioned, there is now a convention to get the cinema and fashion celebrities, to give an opinion on serious subjects. So, they always say that the spirit of Mumbai is that yesterday we were attacked and today morning we are all normal. The resilience of Mumbai is the only

spirit of Mumbai. Well; resilience is a good thing. Plurality is a good thing. To come back to normalcy is a good thing. Not retaliating is a good thing. But that alone can't be the spirit of Mumbai. The spirit of Mumbai can't be that it gets attacked repeatedly and then gets ready to wait for the next attack. This is the sad history of Mumbai. The real spirit of Mumbai has to be that it has to influence each one of us, those in Government, those in Opposition, those in building public opinion in this country, to resolve, to have a system in this country where nobody really dare attack Mumbai ever again or, for that matter, any other part of India. If the spirit of Mumbai can lead us to that destination, I think, we would all be discharging our national responsibility much better. The question which then arises is: If you are to reach that destination, that this should be the last attack and that Mumbai should never be attacked again or any other part of India should never be attacked again, then, how do you fight this menace of terrorism? You don't fight it by dividing ourselves into categories of 'your terror' or 'my terror'.

Sir, I have always believed that the first essential condition required for any society to fight terror is: does it have the political will to fight terror? I have always believed that after 9/11, not many have dared attack Manhattan or, for that matter, United States ever again. Yesterday, we were at a function where the Home Minister corrected me by saying that the attack did take place. But there is a serious doubt about that whether that was because of an association with a radical organization or because of mental illness. I won't get into that controversy. But there are societies which have been targeted by terrorists and which have shown a resolve and determination to make sure that they are never attacked again. Terrorists may still slip in. No security system can be foolproof.

But do we have that political will? Every time we have a policy, somebody decides to pull down that policy. And I have not the least doubt that we must finally have to make a choice: will India's national security and internal security be guided only by security consideration or will it be guided by other collateral facts? You take a hard line on national security, and that is a correct line to

take; then, you will have, for some time, to abandon this thought as to who it hurts. It must hurt only those who indulge in these acts. Those who do not indulge in these acts have nothing to fear about. There is some kind of compromise which takes place with our own freedom and our own human rights. We all do not like being frisked wherever we go. But we are in a vulnerable society which can be repeatedly attacked. There are precautions that the society and the system has to take. Let us not, then, get up and say, "Well, you take this step. This step is, ostensibly, against terrorism but it is intended against a community". No aspersion should be cast on a community; it should only be against the terrorists. And to the extent that you need hard measures, even if they compromise a little with our human rights, then, you will have to take hard measures, and you must have the political will to take those measures.

Sir, a determination to counter terror will have three steps essentially. The first step is your security and intelligence system which prevents terror. Your second step is: if despite that a terrorist attack takes place, your ability to contain that attack. The third step is: you must have a tough and a fair system so that you are able to inflict, after an honest investigation, a punishment on the man who does it, and that punishment, then, ends up acting as a deterrent for others who want to commit terror.

Therefore, we must have the system, both Intelligence and security, to prevent a terrorist act, to contain an attack when it is on, with our Quick Response Teams and so on. There are several questions. Then, of course, the hon. Foreign Minister is here and we have the privilege of his presence at the moment. Our foreign policy considerations, Sir, also have to factor this in mind that we have to effectively use our foreign policy as an instrument to isolate those nations and societies which make terror as an instrument of their State policy. Sir, let us honestly introspect. As a society, have we shown our political will? And when I am saying this, I am not only referring to politics, I will refer to other instruments of Indian society also. Much was debated just now about POTA and TADA. An anti-terror law only comes in after the act is committed.

It does not prevent a terrorist attack. After a terrorist act is committed, you investigate under special powers; you give a punishment to the person and that punishment will act as a deterrent so that in future the act is not committed again. That is the objective of the law. An antiterror law is not a replacement for an intelligence agency. It is not a replacement for the security personnel. Those people will do their tasks separately. Let us look at our own track record and let me give a few illustrations. The late Shri Rajiv Gandhi, when he was in power, brought in TADA. At that time, we had a problem in Punjab. Even the serious problem in Kashmir had not started; it was around mid-80s. The present Home Minister was then Internal Security Minister, and he had piloted the law. It was completely well-intentioned because terrorism was raising its head in this country. There were complaints that in some parts of India it was misused; it could have been amended to stop the possibility of its abuse. Nobody then said, 'repeal it'. This law was then not against any community. The maximum misuse took place in the late 80s in Gujarat, where farmers were arrested under this law. Then, somebody stepped in and said, 'you cannot use it against farmers.' It was used in Punjab, it was used in several other parts of India. It was used in Assam. You had insurgency in Assam in those days. Finally, it was used in 1993 in the Mumbai blasts. Now, the 1993 Mumbai blasts were admittedly terrorist acts; you had a series of blasts at various places. Overnight, you found a campaign for a repeal of TADA because it was used in Mumbai. The Narasimha Rao Government had no option because of this campaign, and that had to repeal TADA. When the next anti-terror law came, you said that it is anti-secular; it is anti-minority. Look at some of the more serious cases. And this is not for punishing the innocents. Home Minister is a very eminent lawyer. Look at the Parliament attack case. But for some of the special provisions in that law, but for an anti-terror law, which was applicable at that time, you would not have been able to convict the terrorists.

Look at the Akshardham case. I always believe that even though, finally, the accused were convicted only under the IPC in the assassination case of late Shri Rajiv Gandhi, the rules of evidence

of TADA were used by a logic that the Supreme Court gave. And it is only because those rules of evidence were used that some people could be convicted for the assassination of late Shri Rajiv Gandhi.

So, the moment the political pressure started, other considerations came in and you said, 'We have to repeal the law.' Today, look at the campaign. What is the campaign? "Withdraw the Armed Forces (Special Provisions) Act." You have insurgency but you cannot withdraw the Armed Forces (Special Provisions) Act. Even if you withdraw the Army from some regions, you will have to keep the State Police; you will have to keep the CRPF. All that the law says is that before you prosecute a police officer or an army officer, you need a sanction. So, the whole objective is to remove the sanction so that those who are involved in separatist activities in the Valley can start endlessly prosecuting the army officers and the police officers! Let the Home Minister tell us how many applications for sanction are pending today with the Governments, State and Centre. Give them a free hand to prosecute. Then, we start saying, "Oh! It is absolutely a law which requires to be withdrawn!" How do you fight an organisation like Lashkar-e-Taiba? Unless we delink this fight from domestic politics and look at it only as a security concern, how do we fight? Today, this is not the occasion, but I will only refer to it and not discuss it in detail. You have the case and the Home Minister knows it well.

He and I will probably differ in our final assessment, in whose connection a Central Intelligence has warned the States as an LeT operative. When the States succeed in an action against them, the Central Government supports the State action, and then politics prevails. You withdraw the affidavit of the Central Government, replace it by an affidavit. And, accordingly, if you remember, what happened, the Lashkar-e-Taiba in its website said, "So and so has become a shaheed, one of our activists." When the Central Government withdrew the affidavit, the Lashkar-e-Taiba also withdrew the obituary. Sir, this is not the way how terror is to be fought. When we start blinking, then the others realise that this is a State which can blink on pressure, one or the other. I am conscious

of the kind of pressure the Home Minister and his Government has had to face on the Delhi encounter in Batla House, an admittedly case of separatist terrorists. You had the NHRC going into the matter; you had the courts going into the matter. They all agreed with his Ministry and his Government's assessment, and yet you had repeated efforts of India's domestic politics, and even the Congress Party's domestic politics, intervening to somehow describe those who were culpable as innocent and describe the security as somebody who is culpable. Instead of visiting the house of the police officer or the security officer who lost his life, people start visiting the houses of those who were being accused. This is not the spirit with which a society is able to fight terror, Sir. What has recently happened? I have no difficulty if you take action against some people who threaten law and order. We have a controversy on. I don't want to give a final opinion on that controversy. Where should one group of citizens sit on a fast from 16th August? The Government feels, "Well, we won't allow the heart of New Delhi, where the other citizens' group had sat on their protest; Ramlila Ground or otherwise. So, Mr. Hazare and Baba Ramdev can't sit at these places. Did we have the courage to show the same spirit where dozen different varieties of separatists came to Delhi and wanted to hold a meeting within yards of the seat of the Central Government? They came here; they came to Lutyens Delhi; they sat here. Before the entire country and the world they made speeches how India is to be broken up. Speeches were made.

They were not only separatists from the Valley, they were separatists of different variety. As though they are forming a union or a confederation, each one said, "The whole idea of India is incorrect. India can never be one country." These were the speeches made. The Home Ministry felt, "No, no, these are the people, whom we should not move out of this place." Sedition -- these were seditious speeches -- was passed off as a free speech. So, our entire liberal approach surfaced when we found these separatists. We will use kid gloves to tackle them, and use harsh means to tackle the 16th August fast or the earlier action which was taken at Ramlila Ground. Now, if this is, Sir, the approach, not only of the

Government, this is the approach of anyone of us, for any colour of terrorism, then that is not how we can really safeguard India's security. Let us look back at 26/11. I only want to urge the Home Minister that the anti-terror policy should not merely be judged from the approach which the Government or his Ministry has adopted in the last 32 months of his tenure.

There has been a long-standing policy and, therefore, let us judge the whole thing. When 26/11 took place, where did we stand at that time? How were we caught unawares? Have you had some Intelligence information before that? Sir, I have been reading a lot of material on this and the situation of India or our security apparatus on 26/11 is best described in the following words. Mr. Chidambaram will find these words very familiar and I am quoting them from his speech he delivered, the Intelligence Bureau Centenary Endowment Lecture on 23rd of December, 2009. This was his own description and I quote him. "The Security establishment was in disarray and numerous questions were being asked. Had the Intelligence failed? Did the first responder, the Mumbai Police, prove to be totally inadequate? Was the famed National Security Guard too slow to get off the block? Did the leadership of the Police let down its own men? Did the Central forces take too long to neutralize ten terrorists? Did the Centre and the State Government fail to provide a strong leadership? Did the management system collapse? Did the country pay a heavy price before it repulsed the terrorist attack? Did the Government fail to believe in mounting a swift counter on the perpetrators of terror." The Home Minister said, "I know the answers but I won't give them." Sir, when no answers are given the reason for not giving the answers is also at times obvious. Undoubtedly, the answers to most of these questions were, 'yes'. He then suggested a vision for the future and his vision for the future had several aspects. He first said, 'Let us first set up a National Investigating Agency.' Some people here and outside the State Government had doubts that the National Investigating Agency may impinge on the federal structure. Some speeches to that effect were also made, but because of considerations of national security we decided to support it. He then suggested that the

Unlawful Activities (Prevention) Act will have to be expanded and according to him the amendments to the Act was an admission that the repeal of the Anti-terrorist Law had left a vacuum. So, barring two major areas of difference, he brought back every provision of quota and I can assure some colleagues who use the words, 'these provisions in a society which is to fight terror are essential'. Then, don't compare them with any law of the past. These are new emerging situations. He then said, "lets have a National Intelligence Grid where everybody who collects information and there are dozens of agencies, has to share that information and that India needs a national centre for counter terrorism." Sir, this was in 2008, and now we are in 2011, and almost three years have passed. Where do we stand? Even the NIA did not investigate 26/11. I am a great personal sympathizer and a supporter of these investigative and Intelligence agencies because of their work being done in national interest, and if excesses are committed by any one of them, the system must be vigilant; we must have checks and balances to correct them. Sir, besides the questions he raised on 26/11, how is it that after investigating the whole case in which several people must have been involved -- look at the system that we have -- we ended up convicting one man?

We have convicted that one man. And, convicting him was no rocket science. He was there with a weapon in front of us all, before the cameras and going about shooting and killing people. He was caught red-handed. And, he, obviously, had to be convicted. Our internal investigative system ended up convicting one man alone for an attack which was, probably, one of the most powerful attacks anywhere in the world after 9/11. It took no time for the FBI in the US to find out who David Hadley was and who Mr. Rana was. We had some evidence about Pakistan's involvement. But, it was really the Chicago Trial which gave us such conclusive evidence in terms of the involvement of both LeT and the ISI. It was these evidences that we got helped us. I am sure there must have been some domestic evidences also. But the trial itself was ended up in convicting only one man. One purpose the Chicago Trial served was that it completely demolished and obliterated the distinction between State

actors and non-State actors in Pakistan. The Let is, ostensibly, a nonState actor. The ISI is a State actor. But, this was completely controlled and the handlers of this attack were in the Pakistan's official agency.

Sir, the National Counter Terrorism Centre has still not become functional; I hope it does. I would only urge the hon. Home Minister one thing. We have followed, through the media, the arguments and the counter-arguments in setting up of the National Intelligence Grid. I am sure, the Government will, in its wisdom, take all steps keeping two facts in mind. And, these are my causes of worry. In any intelligence grid, actionable intelligence intended to be shared. Sharing actionable intelligence has its own dangers; generic intelligence should be shared. But, actionable intelligence, with specifics, can never be put on such grids. You can never put intelligence on the grid that we know who is staying, say in a house in Abbottabad. The moment you did it, it will be counter productive.

One agency may not be willing to share with the other agencies, which is the executing agency. The second one is this. This, I am sure, is what Mr. Ganguly mentioned about the cyber terrorism and those who use cyber space to invade. Unless we are doubly sure that we have built up fire walls around our grids, it is dangerous to put anything on the grid. The leaks in the US are from such grids. They have come and set the entire world to pace. Therefore, when we become over enthusiastic about these grids and sharing of intelligence and putting it on the grid, the need to know must be kept in mind -- who is entitled to know how much, what is not to be shared must also be kept in mind and nothing should be shared till you are able to build fire walls around the sharing mechanism. I hope, all this is kept in mind before these proposals are put into action. As I said, we have the opportunity that Shri Krishna is here. I come to the Foreign Policy initiative. In India's case, in fighting terror, the Foreign Policy initiatives are extremely important. It is an important instrument for us. Sir, unquestionably, three facts are clear. The hon. Minister says that we live in a disturbed neighbourhood. Some hon. Members have said that this is the most dangerous border in the world. The

economists have a cover story almost using the same language. We are a State in the neighbourhood which has used terror as an instrument of State Policy. We have a nation in the neighbourhood which has become an epicenter of global terror. You have a situation where there is hardly a terror attack anywhere in the world, and some news items have initially indicated that in the recent attack in China Pakistan's hand or a Pakistan connection is always there... whether it is the blasts in the underground trains in London or major attacks in India or in the United States or anywhere in the world. Today, we are, for the first time, reaching a situation where there is a global convergence on how you deal with a State, which has a nuclear arsenal, which has terror, which has a lack of positive agenda, and which has a lack of great economic development. How does the world deal with a State of this kind? It is a State which is not merely living in denial. That was something we used to say years ago. Today, it is a State which is living in deceit. They are a friend of America, an ally of America, in America's war against terror. They are, simultaneously, an ally of the enemies of America in the war against terror. It is a State which can perform both roles. One important think-tank in the U.S., one of their important spokespersons talking about our neighbour, recently said, "Pakistan is an ally, not a friend. India is not an ally, but, still a friend." That's how they started looking at us and the situation in this region. The Afghan-Taliban was created and supported, virtually, by the ISI. They still want America to have a dialogue or an entry route for them. The Lashkar-e-Taiba was similarly created as an alternative front which was India-centric. It started the blasts in India. That is where the connection of all this security comes in. When they were found out and action taken in various parts of the world, they kept changing names. Somebody then started operating when there was a different regime in Bangladesh. Huji was there, and the JuD was there. And, then, you had, before the ban on the SIMI took place, -- there were several incidents with which SIMI was connected -- the armed faction of the SIMI or the wing of the SIMI which was organising this. When they were found out and banned, you now

have the Indian Mujahideens. How do we, Sir, use our foreign policy initiatives in combating this? A lot of these activities may even take place by home-grown terrorists and they are externally inspired. Some of these Organisations are externally funded. They are also externally created. Therefore, it is simply said, in the absence of any other alternative, we will continue to engage. The Government sees virtue in engagements. But, please bear in mind that even when you engage, one of the foremost issues you have to raise-- one can always negotiate the side issues which are in the grey areas -- is; what was contained in the January 2004 understanding between them and us? How can there be a fruitful engagement if your territory is used for terrorist strikes against us? You can always engage. Soz sahib just now said, we want a stable Pakistan. Of course, everybody wants a stable Pakistan. We want a stable neighbourhood. But if you get a stable neighbourhood which is more transparent, where there is civilian authority, where there is less radicalisation, it will be always welcome. But if you have a situation where the society gets radicalised, the society continues to use terror, the State instruments continue to use terror, the Armed Forces get radicalised, the civilian establishment gets weakened, transparency in the society goes down. Then, in a such case, the outcome of the engagement will be determined not by the fact that we are talking to them, but it will be determined by what their internal developments are. And those internal developments must come on the right track. Your foreign policy initiatives with them and with the rest of the world must be used to find out how we deal with the society which has all these issues which arise out of this.

Sir, I would urge the Home Minister not to take any satisfaction out of this fact that there have been only two terrorist strikes of this kind during his tenure. These are two main strikes. I am not going into Sheetla Ghat or any of these strikes. I am not going into those details. If you are able to lead the nation and overcome this menace, we all stand in one voice behind you. We wish you all success; this is not a battle we can afford to lose. But the fact is that you have various kinds of problems in this country. You may not call

what has happened in some States in the North East as terrorism; you may call it as insurgency. You may call the Maoist activities as Left Wing extremism. The Indian society and segments within blink when you fight terror. Even in your battle against Maoists, this has happened. We have repeatedly discussed that issue here. I have always said that Maoism is not a poverty eradication programme. This is a violent movement which wants to overthrow India's Parliamentary democracy. Therefore, when States take up the fight against them, we take various kinds of social and economic actions. I don't think there is a dispute. You must develop those regions. You must give tribals the full justice and the benefit of economic development. But, then, to do that, to build roads, to build schools, to build institutions, you need the land free from landmines. And, therefore, when you need it free from landmines, you will have to take some security steps. All of us felt very strongly when you, initially, as Home Minister, in your early days in this Ministry, said that these were the steps we would take. We saw discordant voices amongst your friends. From the Left to the Right, everybody supported you. I do not want to go into the details because we have discussed it at length. But, Sir, we have talked about the weakness of the Indian States in dealing with this. I have dealt with the weakness of our political system and our concern for vote banks. Look at how other institutions look at it. I must confess, Sir, that I am extremely disturbed about what recent pronouncements in this matter have come. We had one precedent and I thought we will wish it away where in Kashmir, our security forces were fighting with the militants who were holed into a place of worship. The Supreme Court decided that how many calories must be fed to the terrorists on each day. Judges don't fight terror; Governments do; security forces do.

Therefore, this was one area where I thought the whole concept, which is so vital to our democracy of separation of powers, was being weakened. When I read, I find that from 1861 onwards, the Police establishment of this country, the security establishment has been aided actively by civilians. The 1861 Police Act, almost 150 years as of today, says that you must have special police officers.

The Home Minister will say that "we are understaffed and we are trying to cover it up." So, from traffic to law and order, members of the community are taken to aid the community, to help the community and to protect the community. What were the Village Protection Committees in Punjab? These are Special Police Officers. So, one or two people in every village will get up and protect the village. Today, in Doda, Kishtwar, Soz Sahib will know, in Rajouri, you have the Village Protection Committee comprising of special police officers. You have had them in Maoist-infested areas. You have them in the North-Eastern States. These are not merely employment generating methods. Now, when I read the observations of the Court on these issues, I don't mind, Sir, repeating what I have said in print. "It appears that instead of leaving security issues to the Government of the day, ideology of the authors of the judgement now becomes the ground for determining constitutionality."

Sir, since this is now the law declared, I am sure, the Minister will have no objection if I read out two or three paragraphs. I am quoting it. These are stray paragraphs. I quote, "People do not take up arms, in an organized fashion, against the might of the State, or against fellow human beings without rhyme or reason. Guided by an instinct for survival, and according to Thomas Hobbes, a fear of lawlessness that is encoded in our collective conscience, we seek an order. However, when that order comes with the price of dehumanization, of manifest injustices of all forms penetrated against the weak, the poor and the deprived, people revolt." So, this is the rationale why people revolt and pick up arms.

The next, Sir, is this, and I quote. "Thus the same set of issues, particularly those related to land, continue to fuel protest politics, violent agitator politics, as well as armed rebellion.... Are governments and political parties in India able to grasp the socio-economic dynamics encouraging these politics or are they stuck with a security-oriented approach that further fuels them?" Sir, I don't think our constitutional mechanism ever took away this responsibility from the Government. Judicial review, enforcement of law is a domain of the court. But what should be the approach,

security or otherwise, is a matter entirely left to the Government. This guides the approach in the matter of how insurgency or leftwing extremism is to be handled. It further says, "Rather than heeding to such advice which echoes the wisdom of our Constitution, what we have witnessed in the present proceedings have been repeated assertions of inevitability of muscular and violent statecraft." So, if people lay down land mines, if they go about killing security staff, demolishing schools, dispensaries, hospitals, roads, it is violent statecraft.

If the Government's policies are anti-poor, the Government should be voted out. The Government should be protested against on the streets. The courts must step in and say, 'the Government must then act as per law.' But the courts will not say, 'this is the reason why people have turned violent and you must go as a Home Minister and offer a satyagrah before them.' Don't use what the court chooses to describe as violent statecraft. They can go about killing people and then you are to be removed for the fallouts.

Sir, I am not reading the entire text. There are other aspects of this which have nothing whether it is a separatist or an unlawful act of a State. Centre or States should really rationalize this kind of an approach, and in a country which is torn by various forms of extremism, today you have a situation where thousands of SPOs all over the country are removed. Now, I am not so sure whether the Home Minister can advise the States and the Central organizations to immediately recruit lakhs of people. The result of this was that within two days of this judgment, the Maoists are now giving to the Special Police Officers conditions for amnesty. The conditions for amnesty are, 'you come and join us, we will leave you.' The dice is loaded in their favour. Sir, when I said the political establishment must not blink, there are various aspects of the Indian State, whether it is the media or it is the Police or the State Governments or political parties or courts or institutions, are we going to allow every establishment to start blinking in a case where 210 districts are influenced by Maoism?

The North-East areas have their own problems in some States, which we are trying to resolve; in Jammu & Kashmir, trouble is

created from across the border, and then, sporadic attacks elsewhere in the country also take place. Now, if the Government or a State Government violates human rights, the courts must step in. That is their jurisdiction, but how they are to fight insurgency is a matter which is entirely to be determined by the policy of the Governments, whether Centre or the State. Therefore, I would like the response of the Union Home Minister and the Government as to how they intend to deal with this situation.

Sir, lastly, as I said, this is not a battle that we can afford to lose. Now, how do we fight it? Do we have the political will to fight it? Are we going to be over-partisan in doing so? Or, are we going to fight it only on the basis of considerations of national security? We must address the causes which cause such a situation. But then, no effort should be made to weaken the will of the Indian society in order to fight this menace of terrorism and separatism. That is why, we are glad that the Foreign Minister is here. That is an important instrument he has at his disposal that could be used. And I am sure, if the Government of the day looks forward and brings out a policy and an approach with the support and in coordination with the States, we can hope that this is the last time that Mumbai or any other part of India is attacked in this manner.

■ ■ ■

महंगाई

## भ्रष्टाचार के कारण आप मूल्यवृद्धि पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे : यशवंत सिन्हा

गत 3 अगस्त को लोकसभा में नियम 184 के तहत महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद व पूर्व केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री यशवंत सिन्हा केन्द्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि महंगाई के सवाल पर सरकार कहती है कि वो मजबूर है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार कभी मजबूर नहीं हो सकती क्योंकि मजबूर सरकारें किसी का भला नहीं कर सकतीं। हम यहां श्री सिन्हा द्वारा दिए गए भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं।

Madam Speaker, I beg to move, with your permission, the following motion:

"That despite repeated discussions on price rise in the House, the burden of price rise on the common man is continuing. Expressing deep concern over price rise, this House calls upon the Government to take immediate effective steps to check inflation that will give relief to the common man."

Madam Speaker, this House has been forced to discuss the burden imposed on the common man, on the Aam Aadmi.

मैडम, महंगाई के ऊपर इस सदन में शायद यह बारहवीं चर्चा है। लगभग हर सेशन में महंगाई के ऊपर किसी न किसी नियम के अंतर्गत चर्चा होती रही है।

जैसे मैंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि ऐसा लगता है जैसे चर्चा हुई, बात

आई, बात गई। उसका असर कहीं देखने को नहीं मिला। इसीलिए इस बार का जो प्रस्ताव है, उसमें यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है – "This House calls upon the Government to take immediate effective steps to check inflation that will give relief to the common man." यानी सरकार इस बार की चर्चा के बाद जरूर ऐसे कदम उठाएगी जिससे आम आदमी को महंगाई की मार से राहत मिलेगी। मैडम, मैं इस बात को गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि यह सदन केवल एक टॉकिंग शॉप नहीं है। हम यहां पर आकर सिर्फ अपनी बात रख दें, उधर की बात सुन लें। यह तो स्कूल की डिबेट में भी होता है। यह सदन स्कूल की डिबेट करने के लिए नहीं है, यह सदन सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए है कि सरकार इस सदन की आवाज़ सुने। यहां जो सुझाव दिए जाते हैं, सरकार उन पर अमल करे और तुरंत कार्यवाही करे।

इसीलिए मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ कि हम आज यह चर्चा करेंगे। चर्चा नियम 184 के अंतर्गत हो रही है। उसके बाद इस पर मतदान होगा। लेकिन मैं आशा करूंगा कि इस चर्चा के बाद जब हम मानसून सत्र में चर्चा करेंगे और फिर शीतकालीन सत्र में मिलेंगे तो उस समय सरकार यह सुनिश्चित करे कि महंगाई के ऊपर दुबारा इस सदन में चर्चा करने की आवश्यकता हो ही नहीं, यानी महंगाई के ऊपर निश्चित रूप से नियंत्रण पाया जाएगा, खास तौर पर खाद्यानों की महंगाई, फूड इनफ्लेशन।

रसोई में आग लग गई। अब कोई कहे कि रसोई में आग नहीं जलेगी तो खाना कैसे बनेगा। इसलिए रसोई में आग तो जलेगी। आग जलने और आग लगने में अंतर है क्योंकि आज गृहिणी आग जला नहीं रही है, उसकी रसोई ही जल गई। रसोई की हर चीज़ उसकी पकड़ से बाहर हो गई है। यहां तक कि आग लगाने वाली चीज़ एलपीजी भी महंगी हो गई है। इसीलिए मैं इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। सदन ने सरकार पर दबाव डाला।

हमारे विद्वान मित्र डा. मुरली मनोहर जोशी जब स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सभापति थे, तब उन्होंने दिसम्बर, 2009 में महंगाई के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा। मैं उसे पढ़ रहा हूँ। I have a Report of the Standing Committee on Finance of December, 2009. I am reading from this Report, it says:

"The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,

which is responsible for formulating price policies and management of inflation at macro level, has obviously failed to intervene timely and squarely to address this burning issue with due seriousness. In such a dismal scenario, the Committee cannot but urge the Government to overcome its inertia and come to grips with a reality of unabated rise in the prices of essential commodities... "

...The Committee would, therefore, strongly recommend that a Comprehensive Food Pricing and Management Policy be formulated not only to provide much needed relief to the common man but also as an anti-dote for the growing economic imbalances in the country."

यह दिसम्बर 2009 में वित्त समिति, जो इस संसद की है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक पालिसी बनाओ। उस काम्प्रीहैन्सिव फूड प्राइसिंग एंड मैनेजमेंट पालिसी का क्या हुआ? इसे दो साल बीतने जा रहे हैं। वह काम्प्रीहैन्सिव फूड प्राइसिंग एंड मैनेजमेंट पालिसी कहां है? क्या सरकार आज इस सदन में बतायेगी कि यह जो रिपोर्ट मेहनत करके सर्वदलीय समितियां पेश करती हैं, उन्हें सरकार में कोई पढता भी है, उसका कोई कागजिजेंस लेता है या हम लोग कमेटियों में काम करके, रिपोर्ट बनाकर आपके माध्यम से सदन में पेश कर देते हैं और उसके बाद वह रद्दी की टोकरी में चला जाता है या रद्दी में बिक जाता है।

मैडम, मुझे खुशी है कि आज सदन में इस चर्चा को सुनने के लिए हमारे आदरणीय अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री जी उपस्थित हैं। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि अर्थशास्त्र में महंगाई को गरीबों के ऊपर सबसे घटिया किस्म का टैक्स कहा गया है। The worst form of taxation on the poor is price rise because वह इससे बच नहीं सकता। इसलिए गरीबों के ऊपर इसकी मार सबसे भयानक होती है। वह कैसे, यह मैं बताता हूँ। वित्त मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। इस साल के बजट में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, वह करीब 6 लाख 64 हजार करोड़ रुपये, यानी साढ़े छः लाख करोड़ रुपये है। दो साल पहले यह साढ़े चार लाख करोड़ रुपये था। अब आप यह आंकड़ा सुनिये। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट बनायी है, जो एक इंडीपेंडेंट संस्था है। वह आर्थिक विषयों पर रिसर्च करती है और रिपोर्ट बनाती है। क्रिसिल की अभी एक रिपोर्ट आयी है कि पिछले तीन वर्षों में, यानी वर्ष 2008-09 से लेकर वर्ष 2010-11 तक महंगाई के चलते हमारा

जो हाउस होल्ड बजट, हाउस होल्ड्स हैं, उन्होंने लगभग छः लाख करोड़ रुपया अधिक खर्चा किया। इसका क्या मतलब हुआ? अगर महंगाई को हमने पांच परसेंट पर कंट्रोल किया होता, तो यह उनके ऊपर भार नहीं पड़ता। लेकिन महंगाई इन तीन वर्षों में आठ प्रतिशत या उससे ऊपर रही। वह 20 प्रतिशत तक भी गयी, तो यह जो तीन प्रतिशत का अंतर आया, इस तीन प्रतिशत के अंतर के चलते आपकी जेब, हमारी जेब और गरीबों की जेब से छः लाख करोड़ रुपया अधिक खर्चा हुआ यानी दो लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष।

आप साढ़े छः लाख करोड़ रुपया सरकारी टैक्स वसूल कर रहे हैं और दो लाख करोड़ रुपया इस टैक्स के माध्यम से आपके पास आया। आप सोचिए, सरकारी रेवेन्यू का लगभग एक-तिहाई इन्फ्लेशन, महंगाई के चलते इस देश के लोगों को, गरीबों को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब आप कहते हैं कि हम इनक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास करते हैं। ग्रोथ ऐसी जो सबको समेट कर चले, बहुत अच्छा है। ये नारे बदलते रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक ये नारे बदलते रहे हैं, कभी हमने कहा – ग्रोथ विथ इक्विटी। कभी हमने कहा – ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। कभी हमने उसको कोई और नाम दिया, आज हम उसको नाम देते हैं इनक्लूसिव ग्रोथ। कभी गरीबी हटाओ का नारा भी इस देश में चला था। अभी गरीबी के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के बारे में इसी सदन में एक प्रश्न आया था और बहुत शोर-शराबा हुआ। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि भारत में पिछले 20 महीनों में जिस दर की महंगाई रही है और खासकर जैसे खाद्यान्नों की महंगाई रही है, उसके चलते पांच करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कई एशियाई देशों का अध्ययन करने के बाद यह कहा कि पांच करोड़ लोग इस महंगाई की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए।

हम इनक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसमें गरीब को शामिल करने की बात कर रहे हैं, हम बहुत गर्व करते हैं इस बात पर कि देश अब एक दूसरे पैराडाइम में चला गया, दूसरे जोन में चला गया, हम आज प्रतिवर्ष आठ-नौ प्रतिशत से ग्रो कर रहे हैं और ग्रोथ से गरीबी घटेगी, गरीब की संख्या घटेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने महंगाई पर नियन्त्रण नहीं पाया, तो उसका यही नतीजा होगा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, यानी और अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे, गरीबी घटेगी नहीं।

वित्त मंत्री जी, मेरे पास इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसे आपने ही सदन में पेश किया था। आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों का भण्डार है। इसी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो बॉटम क्विन्टाइल है, देश की आबादी का जो सबसे नीचे की 20 प्रतिशत आबादी है, वह अपनी आमदनी का 67 प्रतिशत फूड पर खर्च करता है, खाने पर खर्च करता है और अगर रसोई में आग लगी है, तो उस 20 प्रतिशत की क्या हालत होगी? हम ऊपर के 20 प्रतिशत को भूल जाएं, बीच के 20 प्रतिशत को भूल जाएं, ये जो 20 प्रतिशत लोग हैं, जिनके लिए हम लोगों ने अन्त्योदय अन्न योजना चलाई थी, वे लोग आज महंगाई की मार सहते-सहते मिट्टी में मिल गए, धूल में मिल गए हैं।

मैं देखता हूँ अपने संसदीय क्षेत्र हजारीबाग में कि जो बेचारा रोज कमाता है, रोज खाता है, आज वह बाजार में कुछ भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। वह मुझसे आकर शिकायत करता है कि मैं क्या खाऊँ, मैं परिवार कैसे चलाऊँ? मेरे पास उसे समझाने के लिए कोई तर्क नहीं है, क्योंकि मैं उसे यह भी नहीं कह सकता कि देश जो आठ प्रतिशत से ग्रो कर रहा है, तुम उसी ग्रोथ को खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन यह कैसी ग्रोथ है, जो उसे ही खा रही है।

मैं बहुत गम्भीरता से प्रधान मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, केबिनेट के जितने भी लोग यहां बैठे हैं उनसे और रूलिंग पार्टी के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि आज इस सदन में, आज या कभी भी आप गम्भीरता से विचार कीजिए कि हम देश में किस प्रकार की ग्रोथ चाहते हैं, किस प्रकार का आर्थिक विकास चाहते हैं। मैं सिरे से खारिज करता हूँ इस थ्योरी को कि किसी भी कीमत पर ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ का मतलब महंगाई है तो ऐसी ग्रोथ हमें नहीं चाहिए। मैं जोर देकर इस बात को कहता हूँ कि हमें नहीं चाहिए ऐसी ग्रोथ। एकतरफा ग्रोथ किसलिए, मैं इस पर बाद में आऊंगा।

एक तरफ गरीब भुखमरी का शिकार हो डेली बेसेज़ पर, क्या हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं, इस पर सोचना पड़ेगा। मैं बहुत गम्भीरता और अदब से सरकार से यह अपील करना चाहता हूँ कि ग्रोथ के पीछे जो आप पागल हो रहे हो, दीवाने हो रहे हो, उस दीवानगी को थोड़ा कम करो, नियंत्रण में लाओ। यहां हमारे गृह मंत्री जी नहीं हैं। वह आंकड़ों के बहुत माहिर हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे समय में 5.8 प्रतिशत ग्रोथ हुई, हमारे समय

में आठ प्रतिशत ग्रोथ हो रही है। वह भूल जाते हैं कि हमारे समय में महंगाई के ऊपर किस तरह का कठोर नियंत्रण था और आज कैसे हमने उस नियंत्रण को हटा लिया है। **Growth with moderate inflation is acceptable-** अगर बढ़ती कीमतों को हम रोकने की ताकत रखते हैं तो ग्रोथ करो, लेकिन ग्रोथ के साथ-साथ अगर इनएविटेबल है बढ़ती कीमतें। मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए, यह स्वीकार्य नहीं है।

जब यह बात आती है, मैं यह कहूँ कि क्या यह सदन लाचार है, क्या यह सरकार लाचार है, क्या हम इस बढ़ती महंगाई के सामने लाचार हैं, तो मेरा मानना है कि हम लाचार नहीं हैं। मेरा मानना है कि अगर हम सब मिलकर चाहें, सरकार हमारे सुझावों पर गम्भीरता से ध्यान दे तो महंगाई को दो महीने के अंदर नियंत्रित किया जा सकता है। वे उपाय मैं बताऊंगा। लेकिन न केवल लाचार है, बल्कि ऐसा लगता है कि सरकार किर्कर्टव्यविमूढ है। ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, असहाय है। असहाय सरकारें किसी का भला नहीं करती हैं। सरकार कभी असहाय नहीं हो सकती। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन के साथ-साथ एक दूसरा फिनोमिना है, जिसे इन्फ्लेशनरी एक्सपेंशन कहते हैं। आप अपने बयान से इस इन्फ्लेशनरी एक्सपेंशन को और बढ़ा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी कहें, वित्त मंत्री जी कहें, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कहें, क्या कहते हैं, हर दो महीने बाद कहते हैं कि अगले दो महीने में हम महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे। और फिर दो महीने के बाद कहते हैं कि अगले दो महीने में हम महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे।

जो मुनाफाखोर हैं, वे सोचते हैं कि दो महीने की मौहलत मिल गयी है और अब जैसे चाहेंगे लोगों को चूसेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि अब दो महीने तक महंगाई नियंत्रण में नहीं आयेगी।

महोदया, आज इस सदन से संदेश जाना चाहिए कि दो महीने में हम महंगाई के ऊपर नियंत्रण जरूर पायेंगे और कल से सरकार कदम उठाना शुरू करे। **You should have done it yesterday, but please do it from tomorrow.** लेकिन आपको महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए यह देखना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या हैं, तभी तो आप उन कारणों को नियंत्रित करके महंगाई को दूर कर सकते हैं।

अब एक कारण कहा जाता है, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू. बुश, उन्होंने भी कहा और वह हमारे देश में भी प्रचलित हो गया कि

लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं इसलिए मंहगाई बढ़ गयी। लोग खा रहे हैं ज्यादा.....खा रहे हैं ज्यादा। अब आप देखिये, मैं फूड-ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ कि एक तरफ हम दावा करते हैं, माननीय कृषि मंत्री महोदय यहां बैठ हुए हैं, वे कृषि मौसम के बाद, पिछले वर्षों में दावा करते रहे हैं और आंकड़े भी बताते हैं कि उत्पादन का रिकार्ड टूट गया है। आज हम 240 मिलियन टन उत्पादन के आंकड़े पर पहुंच गये हैं, बम्पर क्राप हो रही है। हां, देश की आबादी भी जरूर बढ़ी है और मैं यह आर्थिक सर्वे लेकर यहां आया हूँ। इसमें एक आंकड़ा है कि Per Capita Availability of Foodgrains and Pulses, आप इसे उठाकर देखेंगे तो पायेंगे कि बढ़ती आबादी के बावजूद पर-कैपिता फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी कम नहीं हुई है, वह लगभग उतनी ही है बल्कि ज्यादा है जितनी आज से 20 साल पहले थी। Per capita per day availability is 400 grams (+ five per cent). मैं आपके ही आंकड़े बता रहा हूँ। चाहे वह चावल हो, गेहूं हो या मोटा अनाज हो, प्रत्येक में आपने बताया है कि इस साल जरूरत कितनी है और हमने कितना पैदा किया है। आप दो-तीन मिलियन टन ज्यादा ही पैदा कर रहे हैं, कम पैदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी खाने वाला आर्गूमेंट कहां से आया? इस देश के किसानों के अंदर यह सामर्थ्य है कि पूरे देश की आबादी को खिला सकें, बस आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दें।

मैंने दूसरा आंकड़ा देखा कि क्या सरकार प्रोक्योर कम कर रही है, क्या सरकार के गोदामों में अनाज कम हो गया है? वर्ष 2007-2008 में आपने 40 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया। वर्ष 2008-2009 में आपने 57.7 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया और वर्ष 2009-2010 में आपने 57.2 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया। प्रोक्योरमेंट में कहीं कमी नहीं है।

किसान आपको अनाज दे रहा है और आपके गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। Is it 66 million tonnes, Mr. Agriculture Minister? No, you do not deal with that any more. शायद 66 मिलियन टन, शायद 67 मिलियन टन।

65.5 million tonnes is the quantity of grain lying in Government godowns. साढ़े छह करोड़ टन अनाज सरकार के गोदाम में आज पड़ा है। मैं आपके आर्थिक सर्वे पेज 37 में से कोट कर रहा हूँ।

Madam, the Economic Survey 2010-2011 has this to say, and I am quoting:

"... Clearly, given that the last fiscal year was one of high foodgrain price inflation, we would have expected lower than usual procurement and a larger offloading of stored grains..."

यह क्लीयर है कि अगर हाई इन्फ्लेशन था, तो कम प्रोक्योरमेंट होता और लार्जर आफ टेक होता।

"... But neither of these happened. Evidently, there is ample scope for improvement in our strategy of foodgrain release. The current practice has some systemic flaws..."

Now, I am coming to the crux of the matter- मैं इसके सार पर आता हूँ।

"... Trying to ensure that the procured food is not released at a price which inflicts too large a loss on Government, we have often priced it so high that there were no buyers. Not releasing foodgrain defeats the purpose of bringing down market prices..."

आपका इकनोमिक सर्वे है कि आपने कीमत इतनी ऊंची रखी कि कोई खरीदार नहीं है। आप इस स्टॉक को यूज कर सकते थे, to bring down prices वह आपने इसलिए नहीं किया कि इससे सरकारी घाटा बढ़ेगा। लोग मर जाएं, रात को भूखे सो जाएं, लेकिन सरकारी घाटा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकारी घाटा बढ़ रहा है।

Madam, I am quoting the actual figures. The Government's fiscal deficit was Rs. 1,27,000 crore in 2007-2008- एक लाख 27 हजार करोड़ सरकार का राजकोषीय घाटा था। अगले साल वर्ष 2008-09 में यह बढ़ कर 3 लाख 37 हजार करोड़ रुपए हो गया। Rs. 3,37,000 crore was the Government's fiscal deficit in 2008-2009; in 2009-2010, it was Rs. 4,18,000 crore; and it continues. I think that in this Budget the Finance Minister had projected a figure of Rs. 4,13,000 crore to which he has added Rs. 9,000 crore in terms of additional cash outgo.

सरकारी घाटा जो लगभग सवा लाख करोड़ रुपये था, वह बढ़ते बढ़ते 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और एक ही साल में आपने 2 लाख करोड़ रुपया और ज्यादा सरकारी घाटे से इकॉनोमी में इंजेक्ट किया और आपने देश को समझाया कि यह स्टीमुलस है। ये उत्साहवर्धक कदम उस घण्टाईसिस से निपटने के लिए थे जो अन्तर्राष्ट्रीय, ग्लोबल क्राइसिस हुआ

था। लेकिन उससे निपटने के लिए हमारा जितना घाटा बढ़ा, उसको आप मान लीजिए कि यह स्टीमुलस है। सबको स्टीमुलस मान लें। हर सरकार ने इस अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने के लिए उपाय किये। किसी ने घाटे को कम करने का किया, जैसे यू.के. ने किया। कुछ लोग एक्सपेंशनरी फिसकल पॉलिसी पर चले कि और ज्यादा खर्च करो, डिमांड बढ़ाओ। हमारी सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया कि घाटा बढ़ाओ, उससे मांग बढ़ेगी और सबको स्टीमुलस मान लिया।

अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ कि हम लोगों के समय में फिसकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ कि सरकारी घाटे को नियंत्रण में कैसे रखा जाए। मैं यूपीए-वन की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने सरकार बनाने के बाद उसको नोटिफाई किया। पार्लियामेंट का कानून है और नोटिफाई करने के बाद उस पर अमल करना शुरू किया। उसमें यह था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, उसको आप शून्य पर लाएंगे और फिसकल डेफिसिट को दो-तीन प्रतिशत के आसपास लाएंगे। अब जिसे ये स्टीमुलस कह रहे हैं, उन्होंने इसमें दो-तीन लाख करोड़ रुपये का घाटा बढ़ा दिया। वह आपने रेवेन्यू एकाउंट में बढ़ाया और आपका जो रेवेन्यू घाटा है, वह आपके फिसकल घाटे का 75.2 प्रतिशत 2008-2009 में हो गया और 80.7 प्रतिशत 2009-2010 में हो गया। **Now, the Finance Minister is struggling to bring it down.** इस बजट में उन्होंने 72.5 प्रतिशत कहा है।

अब मैं एक सिम्पल बात आपसे कहना चाहता हूँ। इसमें कोई अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सरकार के एक मंत्री के अनुसार 'We are not even people with average intelligence'.

लेकिन हर एवरेज इंटेलीजेंस का व्यक्ति जानता है कि उसको अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, वह अनप्रोडक्टिव होता है। उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, उससे उत्पादन बढ़ता है। आपने अगर स्टीमुलस में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो जाहिर है कि उससे उत्पादन नहीं बढ़ा। अब कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता था और उसको सोचना चाहिए था कि अगर इतना ज्यादा पैसा हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो उसकी जो मांग जनरेट होगी, उसको मीट करने के लिए हमको कुछ कदम उठाने चाहिए। यानी हमें इंवेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हों। अब उससे इस मांग की पूर्ति हो सकती है। हालांकि यह भी मैं आपको बता

दूँ कि वह जो दो लाख करोड़ रुपया सरकार ने अपने घाटे का बढ़ाया, वह वापस दूसरी तरफ से गया क्योंकि दो लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष महंगाई की मार के अन्तर्गत लोगों की जेब से गया। वही हुआ कि सरकारी खजाने में नहीं गया लेकिन वह जमाखोरों, मुफ्तखोरों, रिश्वतखोरों और मुनाफाखोरों के पास गया। इंवेस्टमेंट नहीं होगा और डिमांड बढ़ेगी तो मिसमैच होगा। महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उससे बचा नहीं जा सकता। मेरे जैसा मंदबुद्धि का व्यक्ति भी इस बात को समझ जाएगा।

तो आपने नहीं लिया और सबसे तकलीफ की बात क्या है, सबसे तकलीफ की बात यह है कि जब यह चल रहा था, महंगाई चरम सीमा पर थी, लोग बिलबिला रहे थे, उस समय सरकार ने रिपीटिडली, बार-बार पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के दाम बढ़ा दिये। अब आप कहेंगे कि आप भी बढ़ाते थे। हां, हम भी बढ़ाते थे, लेकिन आप हमारे समय के महंगाई के आंकड़े उठाकर देख लीजिए और अपने समय के महंगाई के आंकड़े भी उठाकर देख लीजिए। जब आग लगी हो तो क्या आप उसमें तेल डालने का काम करेंगे? लेकिन आपने तेल ही डाला। महंगाई की आग लगी हुई थी और उसमें आपने पेट्रोल और डीजल डालकर उसे और भड़का दिया। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, मैं आपको इसकी एक कहानी बताता हूँ, मैं वित्त मंत्री जी को इसकी कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि वह चुनाव लड़ते हैं। वित्त मंत्री जी 2004 में जब चुनाव थे तो मैं अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में घूम रहा था। हम भी किसी खुशफहमी में थे, हम देश के विदेश मंत्री थे, हमारी बड़ी फोटो छपती थी, जैसे आज कृष्णा जी की फोटो छपती है। मैं हजारीबाग में गांव-गांव घूम रहा था कि मुझे वोट देना, वोट देना। मैडम, क्या आप जानती हैं कि एक दूर-दराज गांव में एक महिला ने हमें रोका और उसने कहा कि बाबू मिट्टी के तेल के दाम तो आप बहुत बढ़ा दिये। मुझे उस दिन इतनी ग्लानि हुई कि यहां बैठकर हम फिस्कल डेफिसिट, फलां डेफिसिट, ठिकाना डेफिसिट करते रहते हैं, उस गरीब औरत की बात मैंने नहीं सुनी थी और इसीलिए हार गया और आज यहां बैठे हुए सारे सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि अगर उसी रास्ते चलोगे तो जो मेरा हाल हुआ, वही हाल तुम्हारा होगा।

एक माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री तो चुनाव नहीं लड़ते हैं।

जो नहीं लड़ते हैं वे सुखी हैं, जो लड़ते हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। चूंकि आपने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लिया, सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, क्या आरबीआई करेगा? इन्फ्लेशन से लड़ने की सारी

जिम्मेदारी आपने आरबीआई के कंधे पर डाल दी। जब आपको कदम उठाना है तो आरबीआई के पास एक ही मॉनिटरिंग पालिसी इन्स्ट्रूमेंट है मुद्रा नीति। अब वह उसे कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। मार्च, 2010 से अब तक आरबीआई ने दस बार श्री जसवंत जी ने मुझे करैक्ट किया कि 11 बार आरबीआई ने इंटरैस्ट रेट बढ़ाया है, 425 बेसिस प्वाइंट यानी 4.25 परसेन्ट जो था, उससे यह बढ़ गया और बढ़ाते-बढ़ाते आज उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा यह हुआ कि प्रधान मंत्री जी आप कभी इन लोगों के बहुत डार्लिंग हुआ करते थे, यह बिजनेस इंडिया मैगजीन पर प्रधान मंत्री जी की फोटो है और ऊपर लिखा हुआ है 'नो कांफिडेन्स'। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बिजनेस इंडिया कह रहा है और उससे भी भयानक बात यह है, मैं आपसे कह रहा था कि इनवैस्टमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए प्रोडक्शन नहीं होगा और देश आर्थिक स्लो डाउन के चक्कर में फंस रहा है।

लेकिन हो क्या रहा है 'इंडिया टुडे' में उन्होंने लिखा है 'गुडबाई इंडिया, वैलकम वर्ल्ड'। भारत के जितने मशहूर कारपोरेट्स हैं, उनकी फोटो इसमें हैं और इसमें कुछ आंकड़े हैं, जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष 2010-2011 में 44 बिलियन डालर्स भारत के उद्योगपतियों ने देश के बाहर इनवैस्ट किया। हमारे देश के अंदर कितना आया? मात्र 27 बिलियन डॉलर ही आया। अब देश का उद्योगपति देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। देश का उद्योगपति अपने धन को बाहर ले जा रहा है। कभी हम लोग खुशी मनाते, आज हमें इस बात की तकलीफ हो रही है कि देश में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। देश के धन का इन्वेस्टमेंट बाहर हो रहा है। अब आप इस पर विचार कीजिए। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़े, तो लगाइए। लिब्रलाइजेशन का यह मतलब नहीं है कि देश गरीबी में गोते खाता रहे और अमीरी हमारे देश के बाहर जाए। यह हमें एक्पेक्टेबल नहीं है। आप हर समय एक मुद्दा पकड़ लेते हैं कि यह रामबाण है, यह पैनसीआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर यह कदम उठा लिया जाए। कौन सा कदम? एफडीआई इन रीटेल। एफडीआई इन रीटेल आएगा तो हमारे यहां कृषि का प्राडक्शन जो बर्बाद हो रहा है, वह बर्बादी रूक जाएगी, कीमतें नीचे आ जाएंगी। देश बड़े सुन्दर भविष्य की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर वॉलमार्ट आ जाएगा। मैं आज इस मौके का फायदा उठाकर सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। अमरीका का दबाव है कि रीटेल में एफडीआई आए। उस दबाव के सामने मत झुकिए। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे पास समय नहीं

है, लेकिन अमरीका और मैक्सिको की इकॉनमी में अध्ययन है कि वॉलमार्ट जैसी संस्थाओं ने कैसे छोटे-छोटे दुकानदारों, मझोलों और किसानों को बर्बाद कर दिया। आप उस चक्कर में मत पड़िए। अभी हाल ही में हमारे वित्तमंत्री जी यूएस गए थे। मैं आशा करता हूँ कि वे उनसे कोई वायदा कर के नहीं आए होंगे कि हम रिटेल खोलेंगे। मैं जानता हूँ कि सरकार को पार्लियामेंट के सामने आने की जरूरत नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि वे एक आदेश निकाल कर फॉरन डॉयरेक्ट इन्वेस्टमेंट 51 परसेन्ट कर सकते हैं। यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन आज इस सदन के माध्यम से सरकार और विदेशी निवेशकों को एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा। इससे कुछ फायदा नहीं होगा। घाटा ही घाटा होगा, नुकसान होगा। मुझे याद है कि सन् 2005 में जब कीमतें बढ़ी, हम सरकार से बाहर हुए, उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था कि यह तो फ्यूचर्स मार्केट पर चलते हैं। जो वायदा कारोबार होता है, उसी के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। यह सन् 2005 की बात है, आज सन् 2011 है, उस बात को छह साल हो गए हैं। अगर वायदा कारोबार के चलते कीमतें बढ़ रही हैं तो वायदा कारोबार को आप बंद क्यों नहीं कर देते हैं। हर जगह यह कहा जाता है कि आप कर के गए थे। अगर हम कर के गए थे then we were managing the economy of surplus. जब सब कुछ इतना ज्यादा था, उसके लिए हमने नीति बनाई थी। आज सब कुछ शॉर्टेज में है तो दूसरी नीति चलेगी। अगर आपका आकलन है कि वायदा कारोबार के चलते कीमतें बढ़ रही हैं तो For God's sake, go ahead and abolish it; for God's sake, go ahead and stop it, we will support you- लेकिन सिर्फ तोहमत लगाने से कुछ नहीं होगा कि आप यह करके गये, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में उसको बना दिया तो हम सात साल हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे कि क्या करते?

मैडम, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा उपाय क्या हैं, सूत्र क्या है? सूत्र है फूड इन्प्लेशन। जब फूड इन्प्लेशन बढ़ रहा था और हम लोग कह रहे थे कि नहीं, ओवर ऑल इन्प्लेशन, कोर इन्प्लेशन, हैडलाइन इन्प्लेशन आदि यह सब बड़ा अच्छा चल रहा है। उस समय मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ने कहा था कि इन्प्लेशन सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता है, इन्प्लेशन लेटर्ली भी ट्रैवल करता है। यानी कि फूड इन्प्लेशन बढ़ रहा है तो बाकी चीजों की कीमतों में भी वृद्धि होगी, इसे ध्यान में रखिये, लेकिन इसे ध्यान में नहीं रखा गया। Laterally,

food inflation has now affected fuels; it has affected manufacturing sector. अगर हम इसे आज के दिन से पकड़ें तो वह सूत्र फूड इंप्लेशन है। आपके पास साढ़े पैंसठ मिलियन टन अनाज है। शायद इसी सदन में, वित्त मंत्री जी को याद होगा, एक दफा बोलते हुए मैंने कहा था, वर्ष 2002-2003 में जब मैं जून में वित्त मंत्रालय छोड़कर चला गया था और हमारे एमिनेन्ट कुलीग जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री बने थे। उस साल देश का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था। रि कॉर्डेड हिस्ट्री, महोदया, जब से हम मानसून के रेन्स रि कॉर्ड कर रहे हैं, देश में इतना बड़ा सूखा कभी नहीं पड़ा था, जितना वर्ष 2002 में पड़ा था। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। हम लोगों ने क्या किया? The situation would have gone out of hand like today it has gone out of hand. हम लोगों के पास भी उस समय 65 मिलियन टन अनाज था। उस 65 मिलियन टन अनाज का हम लोगों ने क्या उपयोग किया, हमने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। आप फूड सिक्युरिटी की बात कर रहे हैं। दो रूपये किलो गेहूँ और तीन रूपये किलो चावल तो हम वर्ष 2002 में फिक्स करके गये हैं। हम फूड सिक्युरिटी प्रोवाइड करके गये हैं। आज आप नौ वर्षों के बाद कहते हैं कि फूड सिक्युरिटी और वर्ष 2002 की कीमत पर हम बेचेंगे, ठीक है। हमने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की, अन्नपूर्णा अन्न योजना शुरू की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज्यादा चुस्त-दुरुस्त करने की कोशिश की। जितने राज्यों में सूखा पड़ा था, उन राज्यों को अपने गोदाम से मुफ्त गेहूँ और चावल हम लोगों ने सप्लाई किया। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स के लिए लाखों टन गेहूँ हम लोगों ने उन राज्यों को दिया। हमारे मित्र डॉ. के.एस.राव यहां बैठे हैं। उन्हें याद होगा कि आन्ध्र प्रदेश में बहुत सूखा पड़ा था, उस समय चन्द्र बाबू नायडू जी वहां के मुख्यमंत्री थे। वे दिल्ली आते थे। लाखों टन अनाज हम लोगों ने आन्ध्र प्रदेश को दिया कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू कीजिये। इतना ही नहीं हम लोगों ने लिबरली सरकारी गोदाम में से गेहूँ और चावल मिलर्स को उपलब्ध कराया, प्रोसेसर्स को उपलब्ध कराया कि आटा बनाओ, मैदा बनाओ, सूजी बनाओ, बेसन बनाओ इत्यादि, लेकिन मार्केट में अनाज पहुंचाओ। हम लोगों ने मार्केट में इतना अनाज रिलीज किया कि वर्ष 2002-03 को रेट ऑफ इंप्लेशन आपके आर्थिक सर्वे के मुताबिक it was only 3.4 per cent- देश की जनता को महसूस भी नहीं हुआ कि देश में इतना बड़ा सूखा पड़ा है। जब मैं स्टॉक्स की बात कर रहा था तो हमारे मित्र यहां कह रहे थे कि गेहूँ सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है। हम रोज टीवी

चैनल्स पर देखते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि सरकार के पास भण्डारण की व्यवस्था नहीं है। स्टेशन पर खुले में अनाज पड़ा है, कहीं सड़क के किनारे खुले में अनाज पड़ा है, बोरा फट गया है और उसमें से अनाज बाहर निकल रहा है।

महोदया, अनाज बाहर निकलकर सड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट रोज सरकार की भर्त्सना कर रहा है, लेकिन हम गरीब को अनाज नहीं देंगे। हम गरीब को अनाज क्यों नहीं देंगे? आप अनाज भेजिये। अगर आपका स्टॉक 65.5 मिलियन टन है, over the next two months, you bring it down to 40 million tonnes. आप 25 मिलियन टन अनाज बाजार में भेजिये और देखिये कि कैसे कीमतें नीचे नहीं होती हैं। एक दफा अगर आपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्राइसेस के ऊपर नियंत्रण पाया तो जितना भी मेरा अनुभव है, मैं उसके आधार पर कहूंगा कि उसका असर दूसरी चीजों के ऊपर पड़ेगा, प्राइस राइज कम होगा और गरीब को राहत मिलेगी। आज क्या हो रहा है? इन्हीं के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल।

जैसे कि बुखार होता है तो 98.6 नॉर्मल होता है, लेकिन कोई कहे कि 200 नॉर्मल है या 100 नॉर्मल है तो यह क्या मतलब हुआ? अर्थशास्त्री कह रहे हैं न्यू नॉर्मल। I would say reject 'new normal'. There is no 'new normal'. This country will not accept inflation of more than 3 per cent. I am not even referring to that. अंत में मैं फिर इकोनॉमिक सर्वे की तरफ जा रहा हूँ। मैं वोट कर रहा हूँ।

"For India to develop faster and do better as an economy, it is, therefore, important to foster the culture of honesty and trustworthiness."

यह इनका इकोनॉमिक सर्वे है, मेरा नहीं है। और यह कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में। I am quoting again:

"So, once you recognize that honesty, integrity and trustworthiness are not just good moral qualities in themselves but qualities which when imbibed by a society lead to economic progress and human development. People will have a tendency to acquire this quality and should build a more tolerant and progressive society." Where is trustworthiness? Where is integrity? Where is honesty? और इसीलिए मैं अपनी बात को अंत करना चाहता हूँ। आप दोबारा सरकार में आए तो आम आदमी के नाम पर आए, आप भूले

नहीं होंगे! आपने कहा – कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ। अब ये छः लाख करोड़ रुपये जो आम आदमी की जेब से गए हैं, जैसा मैंने कहा – मुफ्तखोर के पास गया, मुनाफाखोर के पास गया, जमाखोर के पास गया, सूदखोर के पास गया, रिश्वतखोर के पास गया। क्या आपकी यह सरकार उन्हीं लोगों के लिए चल रही है? क्या आप भूल गए आम आदमी को? अगर यहाँ से भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण नहीं लगेगा तो नीचे सब कुछ खूला रहेगा। वह जो बाल्टी है, उसका कोई पेंदा नहीं होगा, पानी गिरता जाएगा। हमारे मित्र जसवंत सिंह जी बार-बार मुझसे कह रहे थे कि नरेगा का जिक्र जरूर करना। अकेले नरेगा ही क्यों, आज चर्चा हो रही थी कि जितनी बेकार की स्कीम्स आप यहाँ से चलाते हैं, वह सब पैसा जा रहा है लोगों का। And Madam, corruption will only lead to conspicuous consumption. करप्शन का पैसा लोग कहाँ खर्च करेंगे – conspicuous consumption और जब conspicuous consumption as a result of this corruption, you cannot control prices. इसलिए जितने मैंने कारण गिनाए, उसके साथ-साथ मैं अंत में कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार ही महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण है और उस पर अगर आप नियंत्रण नहीं कर पाएँगे तो जैसा कि ओलिवर क्रॉमवैल ने चार्ल्स फर्स्ट को कहा था – "For God's sake go. For God's sake, in the name of God, go." यह सदन बर्दाश्त नहीं करेगा, Go, Go.



CWG

## Involvement of political heads of two governments led to monumental fraud in CWG : Arun Jaitley

*The CAG report has again exposed the nexus of Congress people, government officials and contractors in looting the public money. The situation is such that even PMO and Delhi chief minister Shiela Dixit too stand indicted. All the government documents are pointing towards the fact that a big fraud has been committed under the open patronage of the union government and the Delhi government. Leader of Opposition in Rajya Sabha Shri Arun Jaitley spoke on CWG scam on 09th August 2011. We are publishing the text of the speech hereunder:*

**S**ir, I was referring to the mode and the manner in which the Organizing Committee and its Chairman were appointed. I would just recollect that even though the original bid categorically provided for it being a Government Committee with a Government Chairman, efforts to slip in documents to convert its character did not succeed. Thereafter the IOA President writes to the Prime Minister. On the receipt of the letter and I am just reading a note of 29th October, 2004. This is a letter of 23rd October which is received in the Cabinet Secretariat. The Cabinet Secretary puts up a note to the Prime Minister saying, "Separately a communication has also been received from Shri Suresh Kalmadi, President, Indian Olympics Association for associating IOA in the

Organizing Committee. A view in the matter can be taken after presentation by IOA as mentioned in para 9 of the draft minutes." It is put up to the Prime Minister. The Prime Minister signs this on the 5th of November. Now, it is during this period that something is radically moving. He merely wanted to be associated and his organization to be associated. But, Somehow on the 6th, on receipt of this note, the Prime Minister says and I have already read that note, "Overruling the entire objections of the Prime Minister's Office saying that the Organizing Committee would be headed by the President of IOA and this matter should now be referred to the GoM." The GoM thereafter meets on the 29th of January, 2005 and puts its imprint of approval on the appointment of Mr. Kalmadi as the Chairperson. Later when Minister after Minister is complaining - this is the period when Mr. Sunil Dutt is complaining - it was his two successors who were saying that this is a complete hijack. Is the Government only a milch cow, as one of the Ministers said, which is going to provide the funds without any form of accountability and this would be a private body? What he does curiously is, having received this approval of the Prime Minister and the GoM finally on the 29th of January 2005, now the final hijack of this into a private fiefdom takes place. Instead of a Government society, on the 10th of February, 2005 he goes and registers a private society called Organizing Committee Commonwealth Games, 2010, Delhi.

This is not a Government body; this is a private society. He registers a private society, the Prime Minister and the GoM have already approved his chairmanship of the society and the other members of the society are, at the time of this registration, all who belong to his organization. Therefore, what was originally intended to be a body, appointed by the Government, and a Government non-profit society with a Government chairman became a private society. Even an undertaking in the Host City Contract says, "Even though the games are awarded to the IOA, the Government of India, the Government of NCT and the IOA are all bound by undertaking." And, one of the undertakings clearly was that it will

be a Government society with a Government Chairman because only they could organize it. And, the hijack was, now, complete. Then, Ministers after Ministers start complaining as to what is to be done. I have already referred to Mr. Sunil Dutt's letter, saying, "I find that there is a change of minutes." He writes on 14th November, 2004, "I was surprised to see newspaper reports about a resolution passed by the Indian Olympic Association regarding the appointment of the Chairman of the Organizing Committee, which is at variance with the decision taken in the GoM. The letter of the President, IOA, dated 28th October, 2004, addressed to you, a copy of which was received in my office from the PMO clearly shows that the President, IOA, was aware of the decision appointing a GoM, appointing a Minister." Then, he says, "Notwithstanding the sense of disquiet, I waited for the formal minutes of the GoM meeting, which reached my office on 10th November, 2004, the minutes, as issued by the Cabinet Secretariat, do not reflect the decisions taken in the meeting of 25th October. So, the Minutes are changed." Thereafter, there are letters by which his successor Mr. Mani Shankar Aiyar, then, advises the Prime Minister. He first writes on 23rd October to the Prime Minister's Office, I am quoting, "Without a drastic overhaul of both the Executive Board and the Organizing Committee of the Commonwealth, I fear it will prove to be precisely impossible for the Government to significantly address the excesses of the Chairman, Mr. Suresh Kalmadi." He, then, directly writes to the PM, making a complaint almost to the same effect. Mr. Gill, with his bureaucratic experience, now, starts looking at files as to how this has been hijacked as a private body, which was supposed to be a Government body as the Government was funding that; the agreement was Government, the bid was Government, then, how did it become a private body? Mr. Gill, when he takes over, as late as in 2009, says, I am quoting just one sentence from Mr. Gill's letter, "The then Government of India and the Government of Delhi, along with the IOA, signed the agreement, taking the games, in 2003. The original signed document had a Government

chairman, but later somehow it got changed." So, the Minister was wondering how this Government chairman and Government body got hijacked. Why did it happen? When all this was happening, the three Ministers, in a row, had been complaining as to what was the source of power that this man was wielding that the Prime Minister overruled the Cabinet Secretary, he overruled the Prime Minister's Office, he overruled three successive Ministers, and he overruled what the original bid was. This becomes clear from a letter, when the Ministers are complaining whether they are only a milch cow which is going to fund them and he keeps hijacking the whole operation and spends the entire money and there is no accounting. Mr Kalmadi writes to the Prime Minister's Office, to the Principal Secretary on 31st October, 2007. He responds by saying, and that is where he indicates that where his powers yield from, "The OC, under the Chairmanship of Mr. Suresh Kalmadi and with a fifteen member Executive Board, was registered as a society under the Society Registration Act, 1860, on 10th February, after a series of discussions with the PMO, Chairperson of the UPA and the GoM."

I am repeating, Sir, that the Government's own understanding always was that this is a Government society, not only under the NDA Government, but even under the UPA Government. These are the documents which are freely available. Ordinarily, I would not have referred to them. I had no access to them. But now these are available on the net. One of the funding proposals goes to the Cabinet. A note is circulated to the Cabinet on 21st March, 2005. They compare the bids - this is till 2005 in what is given to the Cabinet -- they compare the Hamilton Bid and the Delhi Bid. The Delhi Bid, in the papers circulated says: "Delhi's Organising Committee will be a non-profit Government-owned registered society, chaired by a Government nominee. The projected games time workforce will comprise 1,990 paid staff and 18,000 volunteers." So, even in 2005 when you are doing all this, you were clear that this had to be a Government body.

Now, where did this pressure come from that sometime in

October, November and December, 2004, you completely allowed this hijack to take place; converted what was to be a Government society, headed by a Government chairperson, and allowed it to be a personal fiefdom of some individuals. Now, Mr. Maken would have us believe that, well, there is something in the Host City Contract. In none of these documents -- I am referring to the Cabinet notes, Cabinet Secretary's notes, Ministers letters, Prime Minister's note - any strength is drawn from the Host City Contract because the Host City Contract was as clear as daylight. Games are awarded to the IOA. The IOA, Government of India, and the Government of NCT are bound by their undertakings, which is the bid document. And the bid document was that this is going to be a Government-owned registered society with Government nominee as the Chairman and IOA nominee as the Vice-Chairman. Now, Sir, I would like to put a question. Was he a chairman in his private capacity, or, was he a chairman as a Government nominee? If he were chairman as a Government nominee, then, why was it allowed to be registered as a private society? So, the private society of which he and his friends are the owners, they run it; the Government lends its shoulder to him to become a chairman. This House is not informed about a single document. So, while this matter is serious, has the Government, through the Minister's statement, told us that this appointment was made by the GOM, this appointment was made by the Prime Minister's Office? Nothing is told to us. Therefore, Sir, to make this debate meaningful, -- the country is entitled to know the entire facts on the structure of these games -- at least, the papers should be placed in the Chairman's Chamber or before this House. The whole country is entitled to see what the documents are. I have no hesitation in saying that if you don't place these documents - there are only some which have reached us - there are going to be a lot more in those files which are going to reveal the truth which the Government does not want to come out with. Now, Sir, the eventual test was when in 2010, after the games, scandals erupted, and Mr. Kalmadi had to be removed. Who removed him? If he was the private

chairman of a private society, the Government of India had no power to remove him. All of us are associated with societies in our private capacities, Governments cannot remove us. Governments can remove us only if Governments have appointed us.

The Government now wakes up to the truth and refers the matter to the Attorney General of India. The Attorney General, in January, 2011, gives an opinion saying, "We now realized that it was a private society, but he was appointed as Chairman by the GoM; so, the Government of India is within its right to remove it." So, the final law is made when the Attorney General's opinion comes that he can be removed by the Government of India because it is the Government of India in 2005, which had appointed him. Now, Sir, as a Chair, you are the protector of this House and its rights. A statement has been made before this House, which, essentially, has only limited information. There was a Host City contract. The bid got, for some reasons, altered - whether it was an interpolation, whether it was a fabrication, and before which, Sir, our hands were tied. The whole history of its strangle hold on the Organizing Committee and the money spent by persons outside the Government is completely concealed. Is this House to be kept in the dark or is this House to be informed? And, if this House is to be informed, then, I think we are being unfair to poor Mr. Maken. He has committed no impropriety. He has just been put up here after the newspapers reported that the finger is pointing to the Prime Minister's Office for having appointed him, for having made a hurried Statement and that hurried Statement is that you must simply say, "Nobody had anything to do; it was only the previous Government which had done all this." Sir, you will have to take a call whether this House is entitled and the people through this House are entitled to know the truth or not. Or, are we only entitled to know convenient Statements made by Ministers? Now, look, what happens after this. Every contract which is executed by this private body--they function, essentially, on Government money; they function on tax payers' money-and implemented is over priced. I am not only on the procedural improprieties.

compare it with the costs. For the last one year, we are being disgraced by fact after fact before the global media that every contract is overpriced and there is no scrutiny. Today, the CBI is working overtime to find out the truth. Once this kind of a leeway starts that the Organizing Committee can do it, then, obviously, what has happened elsewhere is not untrue either. We all live in a real world and we know in the real world how much stadiums cost and how much beautification drives in the host city costs. Compare the cost of these stadiums with the stadiums built elsewhere in the country. So, I can tell you, except for the recently renovated Mumbai, the Wankhede Stadium, there is not a single cricket stadium in India, cost of which has gone into three figures. They are between Rs.40 to Rs.80 crores. They are considered as good as the best in the world. You have had the World Cups, you have had more games there than any other part of the world. Jawahar Lal Nehru Stadium renovation cost Rs.961 crores. Dhyan Chand Stadium -- Pandit ji built it at the time of First Asian Games-- from 14,000 to 17,000 is the capacity expansion, 3,000 seats are increased- cost Rs.350 crores. Dharamshala has, probably, one of the most beautiful cricket stadiums in the country -- Rs.48 crores, including land cost. You compare the cost which the Commonwealth Games have cost us. You compare it with each one of the contract. The NDMC had to build the Shivaji Stadium, it is still not ready. Seven colleges of Delhi University were told, "Don't admit students in the hostel for the first few months. Hostels will be renovated and guests will come and stay here." Each college was given huge grants, because practice facilities will be held.

Now, we happen to know some of those colleges. In fact, I am associated with one of them in the management. So, I asked them, 'how were the practice facilities held?' Six months after the Games were over, the work was still going on. No practice was held. How many guests came and stayed in the hostels from which students were evicted? Not one; not one. You evicted all the students from the hostels of the universities because guests will come and stay. This is how the money is to be spent. You lay the

pavements; then you pick them up and say, 'I don't like the colour.'

Sir, as far as the agencies are concerned, the agencies will be accountable to whoever in law the agencies are accountable, whether it is the CPWD or the Sports Authority of India and other agencies. The political heads of the Government, whether it is the Delhi Government or it is the Government of India, are responsible to both Houses of Parliament. Delhi is after all a Union Territory though they have their own Assembly; but it is a Union Territory. The political establishment is accountable to this country. You created a system in which, in a whimsical and fanciful manner, works are going on overpriced; the Central Government is a little worse, because, you created a mechanism for the Games which was contrary to all arrangements.

Sir, every Commonwealth Game, every Olympic Game, every Asian Game is awarded to the Association. Mr. Maken should know this. But there is always a Government-headed Organizing Committee because Governments pay, taxpayers pay. The Sydney Olympics had a Government-headed Chairperson. The 1982 Asiad, first had Mr. V.C. Shukla and then had Mr. Buta Singh. The Afro-Asian Games during the NDA period was done by the IOA; it was held in Hyderabad and Mr. Chandrababu Naidu was the Chairman. This is the arrangement which was to take place and which has taken place in the history all throughout. And, instead of that arrangement, you created private systems and, therefore, Sir, there are two issues which I raise and with which I conclude. My colleagues may refer to some other questions with regard to the final details of this. The first is, the Government has not taken this House into confidence. They have not been candid with all facts. They have given us a twisted version of the facts that 'because of some contract we were bound', though that is never referred to, from 2004 to 2007. The real truth is, you saw a political ally in the gentleman and handed over the Games to him by turning and twisting all the contracts. And the second fact is, it is for the Government to decide what they want to do. We, as the Opposition, are very clear that political heads of the two

Governments which were involved in this and because of which this monumental fraud has taken place, these huge cases of overspending of public money have taken place, don't have a right to be in their offices even for a single day more.... It is only when these heads roll that India's democracy will be held to be more accountable. Sir, if I had stated any fact which is inaccurate, we, at least, have three former Sports Ministers present in this House today to point it out. I am sure, from 2003 to 2010 those who looked after these Departments are here, barring Mr. Sunil Dutt. They will know the facts which I mentioned. Even if there is a slight inaccuracy in what I have said, it can be pointed out. Otherwise, the Government must be hauled up for making an inaccurate statement of this kind which the Minister has a lot to answer on these questions. Thank you.



## घोटाले होते रहे, प्रधानमंत्री देखते रहे : यशवंत सिन्हा

राष्ट्रमंडल खेल घोटाले पर लोकसभा में हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद यशवंत सिन्हा ने यूपीए सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार दोहरे मानदंड अपना रही है। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन में जो लूट-खसोट हुई उसके बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को सब पता था, इसके बाद भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। हम यहां श्री सिन्हा के भाषण का संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:—

सभापति महोदय, मैं अक्सर इस सदन में अपनी बात बहुत आत्मविश्वास के साथ रखता हूँ लेकिन आज मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। क्यों डरा हुआ है, वह इसलिए कि हमारे सामने हमारे नौजवान दोस्त, खेल मंत्री, श्री अजय माकन जी बैठे हैं, मैं इन्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। हमारा इनका बहुत स्नेह का रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी में हमारे बहुत मित्र हैं लेकिन कल मैं देख रहा था एक टीवी चैनल में, इन्होंने विपक्ष को धमकी दी और यह कहा कि मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं और मैं कल विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलूंगा।

मुझे लगा कि मुझे संसदीय परम्पराओं का जो ज्ञान है, उसमें विपक्ष को तो यह अधिकार है कि हम सदन और सदन के बाहर अपनी बात रखें लेकिन मंत्रियों को यह अधिकार नहीं है। मंत्री अपनी बात सदन में रखते हैं और सदन के बाहर कोई मंत्री अपनी बात कहता है जब सदन चल रहा हो, तो वह सदन की अवमानना होती है।

महोदय, मेरे संबंध में बात कही गई है, इसलिए मैं एक मिनट बोलने का समय चाहता हूँ। मैंने जब लोकसभा में अपना बयान देना चाहा, तो मुझे बोलने नहीं दिया गया। मुझे मजबूर हो कर सदन के पटल पर अपना बयान रखना पड़ा। मैं यहां से राज्यसभा अपना बयान देने के लिए गया, मुझे वहां भी बयान नहीं देने दिया गया और मजबूरन मुझे अपना बयान सभापटल पर रखना पड़ा। उसके बाद अगले दिन मुझे कहा गया कि आप आइए, आपसे राज्यसभा में एक्सप्लेनेट्री क्वेश्चयन-आन्सर्स पूछे जाएंगे। मैं शाम को पांच-साढ़े पांच बजे तैयार हो कर वहां गया, लेकिन शाम को श्री एस.एस. अहलूवालिया के द्वारा मुझसे कहलवा दिया गया कि आज नहीं हम फिर कभी पूछेंगे। अगले दिन मैं फिर गया कि आप मुझसे एक्सप्लेनेट्री क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। उस समय भी मुझसे नहीं पूछा गया। जब-जब बार मैं कह रहा हूँ कि मैं सदन में जवाब देने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद कल मैंने कहा कि मेरे पास उत्तर है और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप मेरी बात सुनिएगा, तो आप महसूस करेंगे कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की पोल खुलेगी, इसलिए आपको मेरी बात जरूर सुननी चाहिए।

महोदय, मैं सदन की परम्पराओं की बात कह रहा था। मैंने अभी यील्ड किया, जब मंत्री महोदय खड़े हुए, तो मैं बैठ गया और मैंने उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया। इस सदन में जब हम दूसरे सदन का जिक्र करते हैं, तो नाम नहीं लेते हैं बल्कि दूसरा सदन कह कर सम्बोधित करते हैं। इन्होंने राज्यसभा का नाम लिया और श्री अहलूवालिया जी का नाम लिया। श्री अहलूवालिया जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं और एक बार फिर इन्होंने संसदीय परम्पराओं का हनन किया है।

महोदय, सदन में जो चर्चा हो रही है, वह मंत्री जी ने जो वक्तव्य 2 अगस्त, 2011 को सदन में दिया या रखा, उसके ऊपर हो रही है। हमारे विद्वान मित्र श्री मनीष तिवारी अभी बोल रहे थे और उन्होंने सीएजी के क्या अधिकार हैं, इस बात से अपनी चर्चा शुरू की थी। उन्हें याद होगा, जब हम लोग सरकार में थे और ताबूत के ऊपर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईश्वर जल्दी स्वस्थ करे, उस रिपोर्ट को लेकर श्रीमती सोनिया गांधी पूरे देश में घूम रही थीं। उस समय क्या इन्हें याद नहीं था कि सीएजी का अधिकार क्या है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां बिहार और झारखंड में एक कहावत है कि मीठा-मीठा गप-गप और

तीखा—तीखा थू—थू। ऐसा नहीं चलेगा। अगर स्वीकार करना है, तो सभी सीएजी की रिपोर्ट को स्वीकार करें अगर स्वीकार नहीं करना है, तो सीएजी के अधिकार पर कोई बात मत उठाओ। मेरे वरिष्ठ साथी श्री जसवंत सिंह जी अभी मुझे बता रहे थे कि संविधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों के ऊपर इस सदन में हम विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत ही चर्चा कर सकते हैं। अचानक सीएजी के ऊपर, जो आपको सूट नहीं करेगा, उस संस्था को आप मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो वह पब्लिक एकाउंट्स कमेटी को जायेगी और जो रिपोर्ट पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में जाती है तो ये लोग वहां क्या करते हैं कोई यहां उठकर बोले कि जेपीसी और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का क्या करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए वैधानिक ढंग से चुने हुए पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष का इस्तीफा बाहर मीडिया के सामने जाकर मांगा जाता है।

क्या यही शोभा देता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ बोलेगा तो यह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे, सीएंडएजी इनके खिलाफ बोलेगा तो यह सीएंडएजी के खिलाफ बोलेंगे, सीवीसी और सीबीआई इनके खिलाफ बोलेगी तो यह उनके खिलाफ बोलेंगे और पीएसी इनके खिलाफ जायेगी तो यह पीएसी की धज्जियां उड़ायेंगे। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं।

Mr. Chairman, this is not the first time that the Congress Party is doing this, namely, playing with the Constitution and the institutions of this country. They have done it in 1975 and paid the price.

Once again they are going to pay the price for what they are doing to destroy the institutions of this country.

सभापति महोदय, मैंने आपसे कहा था कि मेरे बड़े सारे मित्र कांग्रेस पार्टी में हैं। उसी तरह के एक मित्र ने मुझसे कुछ दिन पहले कहा कि इस सरकार ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है और वह स्ट्रैटेजी क्या है, वह स्ट्रैटेजी यह है कि जब हम लोग कोई भी मुद्दा उठाएं तो उसे कहीं न कहीं छोटी सी बात में फंसा दो और इस सरकार के कुछ मंत्री हैं, जो सारे कागजों को देखते हैं और सारे कागजों को देखने के बाद कोई छोटा सा एक मुद्दा कहीं पर पड़ा है तो उसे पकड़ लेंगे और सारी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप आज की डिबेट को देखिये, आज की डिबेट में क्या हो रहा है, मंत्री महोदय ने दो अगस्त को जो बयान दिये थे तथा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे

में बयान दिये थे, आज की डिबेट उसके बारे में हैं।

आज की डिबेट है कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, कॉमनवेल्थ गेम्स की लूट—खसोट के ऊपर और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो डकैती हुई है, उसके ऊपर है। ये बात को कहां ले जा रहे हैं? सुरेश कलमाडी को किसने अपॉइन्ट किसने किया। किसने अपॉइन्ट किया? सुरेश कलमाडी है कौन?

आप उनके साथ सेन્ટ्रल हॉल में बैठे हुए देखे गए थे, इसलिए आप उनके लिए दोषी हैं। ऐसे हुआ था, उसके लिए आप दोषी हैं। श्री विजय कुमार मल्होत्रा के बारे में क्या छप गया, उसके लिए उनका नाम लिया जा रहा है, जबकि वे इस सदन में नहीं हैं।

इस तरह सारे मामले को डाइवर्ट कर दो इस डिबेट में कि सुरेश कलमाडी को किसने अपॉइन्ट किया? सुरेश कलमाडी को सन, 2009 में लोकसभा का टिकट किसने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? सुरेश कलमाडी को ढोते रहे, ढोते रहे, सिर पर बिठा कर घूमते रहे। आज वही सुरेश कलमाडी भारतीय जनता पार्टी का हो गया? जब वह तिहाड़ जेल चला गया तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो डिबेट शुरू करने की कोशिश की है, उसमें कोई दम नहीं है और न हम उसके विस्तार में जाना चाहते हैं क्योंकि वे डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे तो मेरे पास कागजात बहुत हैं। श्री सुरेश कलमाडी को, जो कि आज इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, बेचारे तिहाड़ जेल में हैं, अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए, हालांकि वह बिल्कुल गलत है कि उनको एनडीए की सरकार ने अपॉइन्ट किया था, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन आपने उनको हटाया क्यों नहीं। आपके लिए हमारा बनाया हुआ इतना महत्वपूर्ण है, तो आप खाली कीजिए हम वहां पर आते हैं। जब आप काबिल ही नहीं हैं, आप सब हमारे ही फैंसले पर चल रहे हैं, तो क्यों न हट जाओ। लेकिन जब सुरेश कलमाडी बदनाम हो गए किसी फिल्म में गाना था, सलमान भाई यहां पर बैठे हुए हैं, फिल्म के बहुत शौकीन हैं। जब सुरेश कलमाडी की मुन्नी जैसी हालत हो गई तब उन्होंने आज के अटर्नी जनरल श्री वहानवती का ओपिनियन मांगा, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने कहा है कि "The Attorney General said that Kalmadi was appointed as the Chairman of the OC on the recommendation of the Group of Ministers and hence a call to terminate his tenure as Chairman

could be decided by the Government." Which Group of Ministers? Their Group of Ministers. इस एडवाइज के आधार पर आपने सुरेश कलमाड़ी को कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से हटा दिया। The Commonwealth Games Organizing Committee's work is still in progress. There are still pending bills. जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को तय करना है, लेकिन इन्होंने उसे हटा दिया। वर्ष 2011 में ये उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन वर्ष 2004 में नहीं हटा सकते थे, वर्ष 2005 में नहीं हटा सकते थे। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक प्रोटोकाल के अन्दर लिखा हुआ था कि आई.ओ.ए., इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन इसे एप्वाइंट करेगा। उसमें भी यह नहीं लिखा हुआ था कि सुरेश कलमाड़ी एप्वाइंट होंगे या आई.ओ.ए. के चेयरमैन एप्वाइंट होंगे, लेकिन इनके हाथ बंध गये। अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम क्या करते? मेरे पास उस समय के जितने भी कागजात हैं, कहीं पर भी उन सरकारी दस्तावेजों में इस होस्ट सिटी कांट्रेक्ट और प्रोटोकाल टू का जो प्रावधान है, उसका जिक्र तक नहीं है। मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय की नोटिग्स हैं। उनमें कहीं नहीं लिखा है कि एनडीए की सरकार यह तय करके गयी है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हैं। उनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आज अचानक एक खोजी मंत्री पैदा होता है, खोजी पत्रकारिता खत्म हो गयी, अब खोजी मंत्रियों का जमाना है। वे खोजी मंत्री पेपर्स को खंगालते-खंगालते देखते हैं, इसमें पकड़ो और सारा एनडीए के ऊपर डाल दो। वाहनवति ने यह कहा कि आप उसे जब चाहते तब हटा सकते थे। अगर आपने नहीं हटाया तो इसलिए नहीं हटाया कि अकेले सुरेश कलमाड़ी दोषी नहीं हैं, आप सब लोग दोषी हैं, आप सब लोग मिले हुए हैं।

महोदय, मैं जो दो बातें कह रहा था, एक तो अटॉर्नी जनरल ने जो अपना ओपीनियन दिया, उसे मैंने कोट किया। अब मैं दूसरा एक कोट कर रहा हूँ, श्री सुरेश कलमाड़ी के स्वयं के पत्र को जो 31 अक्टूबर वर्ष 2007 को प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री टी.के.ए. नायर जी को लिखा गया। उसकी प्रति मेरे हाथ में है। उसमें वे कहते हैं कि: "Organising Committee under the Chairmanship of Shri Suresh Kalmadi with 15-member Executive Board was registered as a society under the Societies Registration Act, 1860 on 15th February, 2005, after a series of discussions with PMO, the Chairperson of the UPA and the Group of Ministers."

अगर सरकार में से किसी में भी साहस तो वे इसे डिनाई करें। यह

किसके समय की बात है? इसमें जो भी लिखा है।

सारी बातें इसमें जो भी लिखा है, सारी बातें जो लिखा है, उसके बारे में मैं इससे बेहतर शब्दों में इसको नहीं रख सकता हूँ, जितना कि मेरे मित्र, जो कि आज दूसरे सदन के सदस्य हैं, उस समय के खेल मंत्री थे, श्री मणिशंकर अय्यर, उन्होंने 25 अक्टूबर, 2007 को प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा, उसकी प्रति मेरे पास है। उन्होंने क्या कहा? वह मंत्री थे, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ।

श्री सुनील दत्त जी ने एक व्यथा भरी चिट्ठी लिखी। उनकी चिट्ठी व्यथा से भरी हुई थी। प्रधानमंत्री जी को लिखा। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ यही हुआ कि उनकी चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंची और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सुरेश कलमाड़ी को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। मुंहतोड़ जवाब, इसको कहते हैं। अब श्री मणिशंकर अय्यर जी ने 25 अक्टूबर, 2007 को लिखा। बड़ी इंटरस्टिंग चिट्ठी है। कैंब्रिज के पढ़े हुए विद्वान हैं।

कैंब्रिज के पढ़े हुए। बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं और बोलते भी हैं। मैं बड़ी कद्र करता हूँ, सलमान जी की और उनकी भी जो विदेशों से पढ़कर आते हैं, मुलायम सिंह जी! वे बड़े खास लोग होते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा?

He said: "A recent example of this profligacy is the contract signed with Mike Hooper, a serving official of the Commonwealth Games Federation, to appoint him as an international consultant at a cost of Rs.1.5 -2 crore! ..."

माइक हूपर और माइक फैनल दो थे। माइक हूपर कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के पदाधिकारी थे। इनको डेढ करोड़ रुपए पर यहां एक फार्महाउस लेकर उसमें उनको स्थापित किया गया और मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि यानी कि जो फिजूलखर्ची हो रही है उसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया। फिर उन्होंने कहा, आप जो पूछ रहे थे कि एक एपैक्स कमेटी बननी थी। एपैक्स कमेटी जो कि ओवरराइडिंग पावर्स होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऊपर। सारी बात देखने का अधिकार उसको दिया गया था। एपैक्स कमेटी, जिसके कि खेल मंत्री अध्यक्ष होते। श्री मणिशंकर कह रहे हैं:—

"This has happened despite my personal decision to not operationalise the Apex Committee authorized by GoM after Kalmadi's vociferous opposition to the Apex Committee in the

meeting in August 2006 convened at your level. .... "

प्रधानमंत्री जी ने अगस्त, 2006 में मीटिंग बुलाई और उसमें श्री कलमाड़ी ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया कि एपैक्स कमेटी काम नहीं करनी चाहिए और प्रधानमंत्री चुप रहे, कोई फैसला नहीं दिया, जैसा कि नहीं देते हैं और उसके बाद श्री मणिशंकर अय्यर बेचारे ने कहा कि हमने यह तय किया कि हम उसको ऑपरेशनलाइज़ नहीं करेंगे। उसको कारगर नहीं बनाएंगे। उसके बाद उनका रोना क्या है? उनकी पीड़ा वह इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

"But abuse and scorn continue to be heaped at the Ministry in public statements made by the Chairman who stoops so low as to describe us as 'cartoons sitting in one room of Shastri Bhavan'."

यह मणिशंकर अय्यर जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा। हमने उनको स्वच्छंद छोड़ दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई फैसला नहीं किया, तो मणिशंकर अय्यर जी की क्या मज़ाल थी कि वे इसमें पड़ते तो उन्होंने एपैक्स कमेटी को ऑपरेशनलाइज़ नहीं किया। उसके बाद भी सुरेश कलमाड़ी जी मणिशंकर अय्यर जी को कहते हैं— एक कार्टून है जो कि शास्त्री भवन के एक कमरे में बैठते हैं। उसके बाद वे कह रहे हैं।

He is referring to Kalmadi's functioning as virtual dictatorial functioning of the Chairman. यह वर्ष 2007 की बात है। Without making any reference to the Ministry... वे आगे कह रहे हैं कि "If I may mix metaphors, the Chairman sees the Ministry as a milch cow..."... मैं अंग्रेजी ठीक बोल रहा हूँ न! "The Chairman sees the Ministry as a milch cow(दुधारू गाय) to extract as much money as he can, and a rubber stamp to endorse every spending decision he takes, however, outrageous." उनका फैसला चाहे कितना भी गलत, भयानक क्यों न हो, वह यही समझते हैं कि मिनिस्ट्री सिर्फ इसलिए बैठी है कि उनके हर इस प्रकार के फैसले पर रबड़ स्टाम्प की तरह मुहर लगाए। अब उसके बाद उन्होंने कई सारे सुझाव इस चिट्ठी में दिए और यह कहा कि वर्ष 1982 में एशियन गेम्स हुए थे। सभापति महोदय, यह चिट्ठी दिनांक 26 सितम्बर, 2009 की है। इसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि जो एशियन गेम्स वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए थे, उस समय क्या व्यवस्था बनी थी और उस समय उन्होंने लिखा है कि एक बैंक बेन्चर एम.पी. थे, जिनका नाम था श्री राजीव गांधी। उनको अधिकार दिया गया। उस समय श्री बूटा सिंह अध्यक्ष थे, लेकिन अधिकार दिया गया श्री राजीव गांधी को और उन्होंने वर्ष 1982

एशियन गेम्स को एक शानदार सफलता के रूप में कंडक्ट किया। यह उन्होंने कहा और अब इन्होंने वर्ष 2007 में यह कहा कि इसी तरह का इन्तज़ाम हम लोगों को इस गेम्स के लिए भी करना चाहिए। पर, इस चिट्ठी का क्या हुआ? क्या रिस्पॉन्स हुआ? क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं।

अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी हाल में एक खबर छपी। आज श्री मनीष तिवारी जी (द हिंदू) नामक अखबार का जिक्र कर रहे थे। यह दिनांक 05 जुलाई, 2011 का (टाइम्स ऑफ इंडिया) है। इसमें श्री मणिशंकर अय्यर जी का एक बयान छपा है। वे क्यों बयान देने के लिए बाध्य हुए? वे बयान देने के लिए इसलिए बाध्य हुए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पांच पत्रकारों से मिलते हुए, उन्होंने पत्रकारिता से पांच पांडव सेलेक्ट किया, और उन पांचों से मिलते हुए उन्होंने कहा कि हां, शायद श्री मणिशंकर अय्यर ने हमें कुछ पत्र भेजे थे। लेकिन, उनका एतराज आइडियोलॉजिकल था। वे चाहते ही नहीं थे कि राष्ट्रमंडल खेल इस देश में हों। श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा और मैंने पढ़कर सुनाया कि मेरा एतराज आइडियोलॉजिकल नहीं था। मैंने स्पेसिफिक इंस्टंसेज प्रधानमंत्री के ध्यान में लाए थे कि कहां—कहां भयंकर गड़बड़ी हो रही है। कैसे श्री सुरेश कलमाड़ी डिक्टेटोरियल ढंग से फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन कहीं से रिलीफ नहीं मिला और उन्होंने कहा कि This is very, very telling. मेरे पास लिस्ट है जो उस समय मंत्री बने थे और एक श्री सुनील दत्त जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद यह ज्ञात होता है। श्री सुनील दत्त जी दिनांक 23.05.2004 से 25.05.2005 तक मंत्री रहे। फिर उनका निधन हो गया। From May, 2005 to January, 2006, this Ministry was with the Prime Minister of India directly. It was directly with the Prime Minister of India. उसके बाद श्री मणिशंकर अय्यर दिनांक 29.01.2006 को मंत्री बने। जब वे बहुत इन्कवेनिएन्ट होने लगे तो दिनांक 06.04.2008 को उनको हटा दिया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय में इन्कवेनिएन्ट हुए तो उन्हें वहां से हटाया गया। उसके बाद जब यहां इन्कवेनिएन्ट होने लगे, तकलीफ देने लगे तो यहां से हटाया गया और उसके बाद श्री एम. एस. गिल आए और अभी हमारे नौजवान दोस्त श्री अजय माकन हैं।

अब श्री मणिशंकर अय्यर इस वक्तव्य में क्या कह रहे हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा।

I am quoting because this is under quote.

"The first person to tip me off on impending problem was my

immediate predecessor, Shri Prithvi Raj Chavan, then holding additional charge of Sports"

जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थे और अब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हैं।

"He sought me out in Central Hall to warn me that huge sums of money were being spent on CWG without proper sanction or authorisation. So, ironically enough, it was PMO that tipped me off to Kalmadi's improprieties, not I who first informed PMO on transgressions of financial prudence."

इसका मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय को सब पता था, सारी बातें पता थीं और उसके बाद भी वे खामोश रहे। उन्होंने बहुत राहत महसूस की, जब श्री मणिशंकर अय्यर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने तो कहा कि श्री कलमाड़ी बहुत गड़बड़ आदमी है, भयानक गड़बड़ी कर रहा है, तुम सावधान रहना। उसके बाद वे क्या कहते हैं – फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। वे ये कह रहे हैं कि एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में

"My worst moment came when the Additional Secretary (Expenditure) in the Ministry of Finance informed the GoM that Government Financial Rules prohibited the Sports Ministry from releasing the second instalment of Organising Committee grant until the Organising Committee had provided the Utilization Certificate showing 60 per cent of expenditure of the first instalment and examining the conformity of expenditure to purposes for which the grant was made."

मतलब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कम से कम 60 प्रतिशत का युटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन दीजिए, उसके बाद आपको सैकिंड इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। ये सब जानते हैं, जो सरकार में काम कर चुके हैं कि सरकारी जो नियम हैं, वे यही हैं। उसके बाद उनका क्या कहना है कि जो एडीशनल सैक्रेट्री एक्सपेंडीचर थे, उन्होंने इस बात को कहा, ध्यान में लाया।

Then he goes on to say, "FM..." एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हैं।

"Finance Minister arrived late in the meeting after his Additional Secretary had endorsed my stand,". That means, Shri Mani Shankar Aiyar's stand. "On being told of this, FM overruled his

Additional Secretary, and I, Mani Shankar Aiyar, was instructed to release the second instalment even before receiving and examining the Utilisation Certificate."

अब सब लोग कह रहे हैं कि एक कोई घोटाला हुआ, खाली घोटाला ही घोटाला है।

The FM obviously was the present Home Minister. श्री मणिशंकर अय्यर ने यह नाम दिया है। Shri Chidambaram walked into the meeting, overruled his Additional Secretary (Expenditure) and told Shri Mani Shankar Aiyar to release the money.

Then, Shri Mani Shankar Aiyar says, "I wrote to the Finance Minister requesting if Government Financial Rules were not to be observed, perhaps, it would be best for the Finance Ministry to effect releases themselves instead of burdening the Sports Ministry".

उन्होंने कहा कि तुम सीधे रिलीज़ करो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के रास्ते रिलीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके मंत्री ने, उस समय के खेल मंत्री ने अभी बयान दिया।

यह बयान किसी बी.जे.पी. नेता का नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी दूसरे सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उस समय वे स्पोर्ट्स के मंत्री थे। उन्होंने अपनी व्यथा इन चिट्ठियों में और इस बयान में लिखी है।



## मुंबई बम विस्फोट एवं आंतरिक सुरक्षा

### आतंकवाद तभी खत्म होगा जब सरकार कठोर कदम उठाएगी : रविशंकर प्रसाद

मुंबई में 13 जुलाई को हुए बम विस्फोट को लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद श्री रविशंकर प्रसाद ने यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज आतंकवादियों को प्रभावी संदेश देने की जरूरत है कि अगर कोई आतंकवादी आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो हम उसकी इन नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे चूर-चूर करेंगे। प्रस्तुत है श्री प्रसाद के भाषण का संपादित पाठ :-

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज की चर्चा बहुत ही संवेदनशील विषय पर है। मुंबई में 1993 से आज तक 14 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। अभी जो 13 जुलाई को हुआ, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें 17 लोग मारे गए और सैंकड़ों लोग घायल हुए। आज हम आतंक के साये में जी रहे हैं, कब आतंक का नासूर कहां फूट जाएगा, हमें पता नहीं है। आतंकी आते हैं, हमला करते हैं, हम सब चर्चा करते हैं, सांत्वना देते हैं और हम इस साये में रहते हैं कि अगला आतंकी हमला कब होगा। अभी जोशी जी ने हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र किया, काशी में गंगा आरती के समय लोग मारे गए, मैं 2010 की चर्चा कर रहा हूँ, जर्मन बेकरी पर हमला हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बम फटा, बेंगलुरु में हुआ, लेकिन अभी तक किसी घटना के षड्यंत्रकारी को हम नहीं पकड़ सके और न अनुसंधान की दिशा में आगे जा सके।

मुझे याद है कि 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह मुंबई में थे और स्वयं माननीय गृहमंत्री चिदम्बरम साहब भी थे। मैंने

प्रधानमंत्री जी की उस दिन की टिप्पणी को देखा है कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आगे कोई आतंकवादी घटना न हो। उसी दिन मुंबई में माननीय गृहमंत्री जी की टिप्पणी आयी कि भारत के सारे शहर खतरे में हैं। वे सारे स्टेटमेंट मेरे पास हैं, उनका दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब आगे हमले हो सकते हैं और हमले रूकेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। ये हमले बार-बार क्यों होते हैं? आज उधर से चर्चा हो रही थी 1947-48 की, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुंबई में बार-बार हमले होने के तीन सीधे कारण हैं। आतंकवादी बताना चाहते हैं कि हम हैं, हमारी हैसियत पहचानो। **Recognise our visibility. We can do anything we feel like.** दूसरा कारण है, वे यह बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस या बाकी सुरक्षा बल कितने कमजोर हैं, हम जब चाहे उसे भेदकर आतंकवादी हमले कर सकते हैं। तीसरा कारण है कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी-20 में जाते हैं और वित्तमंत्री जी वहां लोगों से मिलने जाते हैं कि हमारी हैसियत पहचानो, तो वे कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत यह है कि हम जब चाहे बम फोड़ सकते हैं और **investors, don't invest in India. It is a security risk country.** इसके लिए 1947-48 में जाने की जरूरत नहीं है और यह सब पाकिस्तान के इशारे से हो रहा है जिसकी एक पॉलिसी है थाउजेंड कट्स। आज जब मैं यहां खड़ा हूँ आतंकवादी का कोई स्वरूप हो, मैं उसका समर्थन करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, जिसके खिलाफ सबूत हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह क्या बात है? हिन्दू आतंकवाद की बात कही जाती है। हमने कभी मुस्लिम आतंकवाद नहीं कहा, हमने जेहाद आतंकवाद की बात कही। इस मुल्क को बनाने में हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई सभी का हाथ है और आतंकवाद के साये में सभी मरते हैं। आतंकवादी हिन्दूओं को भी मारते हैं, मुसलमानों को भी मारते हैं। क्या इससे सिख परेशान नहीं हैं? क्योंकि आतंकवादी यह समझते हैं कि हम हिन्दुस्तान पर हमला करेंगे और हमारे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। **They know they have no penalty to pay for unleashing terrorist attack in India.** उनको मालूम है, उनके आकाओं को मालूम है कि अगर कभी फंस भी जाओगे तो हिन्दुस्तान की राजनीति ऐसी है कि तुमको बचाने के लिए अपने-आप रास्ता निकलता जाएगा। इसका कुछ संकेत हम यहां की डिबेट में देख रहे हैं, यह हमें समझना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मुंबई की घटना हुई, मैं उसका एक फोटो देख रहा

था। एक वैन में पांच-छह लोगों को फँक दिया गया था, खौफ से, खून से सने हुए चेहरे, इंडिया टुडे में भी एक चेहरा छपा है। ट्रेड टावर न्यूयार्क में 9/11 को आतंकवादी घटना हुई थी, उसमें 3 हजार लोग मारे गये थे। यह सवाल मेरे जेहन में हमेशा उठता है कि अमेरिका और यूरोप की टेलिविजन कम्पनियां, रेडिया कम्पनियां हम से अधिक फ्री हैं। लेकिन क्या हमने कभी 3 हजार लोगों की लाशों की कतारें देखीं, खून से सने उनके चेहरे देखे, घबराये हुए चेहरे देखे? अमेरिका में एक कार्यक्रम में था, वहां पर टीवी के लोग थे, थिंक टैंक यूनिटी के लोग थे, मैंने उनसे सवाल पूछा और यह बात 2003 की है, तो उन्होंने कहा "हां" हम आजाद हैं, लेकिन हम अपने रेडियो, टेलिविजन का अवसर, प्लेटफार्म आतंकवादियों को मुल्क में खौफ पैदा करने के लिए नहीं देना चाहते। जब यह समझदारी बनती है, तो अमेरिका में 9/11 के बाद कोई आतंकवादी हमला नहीं होता है। यदि होता है, तो टाइम स्क्वायर पर पाकिस्तान का आतंकवादी पकड़ा जाता है। क्या हम यह समझदारी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? माननीय उपसभाअध्यक्ष जी, whenever there is a debate on terrorism, why do we appear so divided? आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ एक नासूर है, विदेश के इशारे से काम होता है। माननीय गृहमंत्री जी ने बताया था कि we have vulnerable neighbourhood around us, from Afghanistan to Pakistan. तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है? मैं आज बीजेपी की ओर से कहना चाहता हूँ कि आप अपने वक्ता को देखिए और गृहमंत्री जी, इधर की जिम्मेवारी देखिए तथा आतंकवाद को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही कीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम यह वायदा करते हैं। ये हमारे नेताओं ने भी कहा है, यह जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। इधर क्या होता है? एक घटना बटाला हाउस की हुई और उसमें आतंकवादी मारे गए। उस घटना में दिल्ली पुलिस का एक बहादुर इंस्पेक्टर मोहन शर्मा भी मारा गया था, उसको अशोक चक्र दिया। आपके एक महामंत्री हैं, वे मिलने के लिए आजमगढ़ चले गए, क्या संकेत दिया कि पूरी घटना गलत थी। ऐसा क्यों होता है? अफजल गुरु की बात आती है, लेकिन मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, आप भी वरिष्ठ सांसद हैं और आपको भी मालूम है कि जब 2002 में संसद पर हमला हुआ, तब आप भी एमपी थे और मैं भी मंत्री था। सबको मालूम है कि हम सारे एमपी संसद के अंदर एक ब्लेड का टुकड़ा

लेकर भी अंदर नहीं घुस सकते। अगर उस दिन एक आतंकवादी भी पार्लियामेंट में घुस गया होता, तो हम सभी पार्टियों के नेता सेंट्रल हॉल में मारे गए होते। ऐसे में उस आतंकवादी को लोअर कोर्ट से फांसी की सजा हुई, हाईकोर्ट से फांसी की सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा हुई। उसकी review petition rejected: rectification petition rejected फिर भी हम उसको फांसी नहीं दे पाते हैं? मैं आप से गृह मंत्री जी, यह जानना चाहूंगा— I am not as eminent a lawyer as he is, but I have a little knowledge of law which is the rule or proper order passed by the Parliament or by any other statutory authority that there will be a sequencing in the capital punishment award, disposal of mercy petition? यह लाइन से ही चलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से फास्टट्रेट कोर्ट नहीं होता? अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2जी केस को फास्टट्रेक किया, कांस्टिट्यूशन ने फास्टट्रेक किया, होना भी चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि एक साधारण सजायापता की mercy petition और देश के आतंकी हमले के सरगना की mercy petition सात-सात केस पीछे चले, लाइन में हैं, आ जाओ, चलते रहो। यह कौन सा कानून है? अगर कोई कानून है, तो उस कानून को बदलने की जरूरत है, आज मैं यह कहना चाहता हूँ। जब हम यह सोचकर चलेंगे, तो आतंकवादियों को एक संदेश जाएगा कि देश एक साथ खड़ा है, बोलना चाहता है। फिर बात आई इंटेलिजेंस की। वित्त मंत्री जी का वक्तव्य था, "There was no Intelligence input." अखबारों में यह छपा है और मेरे पास उसकी कॉपी है। हम जानते हैं कि भारत के Intelligence में एक से एक योग्य आफिसर्स रहे हैं, and I am very proud of their contribution. There has been a great professional convention in the IB. इतनी बड़ी घटना हो गई, जानकारी नहीं है। यदि जानकारी है तो बताने की हिम्मत नहीं है कि कार्यवाही नहीं होगी। महोदय, 26/11 से पहले स्पेसिफिक Intelligence input था कि समुद्र के रास्ते जहाज आएगा और हमला होगा। उसको क्यों नहीं रोका गया? ठीक है, क्या हम यह मानें कि आज कल Intelligence के लोगों को विपक्ष की सरकारों के ऊपर सर्विलेंस के लिए अधिक काम होता है। एक घटना और घटी, आजाद भारत की जोरदार घटना कि भारत के नंबर-2, वित्त मंत्री के घर पर सर्विलेंस हो रहा है। उनके आफिस में सर्विलेंस हो रहा है, उनके पीएस के यहां हो रहा है और उनको अपनी आईबी पर विश्वास नहीं है। वे अपने

विभाग से कहते हैं कि प्राइवेट स्टाफ लाओं और जांच करो। फिर मामला आगे बढ़ता है, तो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं। फिर उसका जवाब आता है कि किसी ने चुड़ंगम खाकर फैंक दी होगी। हमने बचपन में चुड़ंगम खाई थी, लेकिन इतने वैज्ञानिक तरीके से चुड़ंगम खाकर फैंकी जाती है?

वित्त मंत्री के टेबल के नीचे लाइन की कतार लगी रहती है, उनके पीएस की टेबल के नीचे लाइन की कतार लगी रहती है, किसे मुख बनाया जा रहा है? हमने आईबी के मोराल को तोड़ने की कोशिश की है। I am sorry to say that और यह अनुभव से आया है। सभापति जी, दिल्ली पुलिस के पदाधिकारियों ने मुझे कहा कि अगर मोहन शर्मा नहीं मारा गया होता तो बाटला को लेकर इतना अधिक जूनून पैदा होता कि हम लोग प्रोसिक्यूट हो जाते। अस्सी के दशक में, जब पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, चिदम्बरम साहब, पहले भी गृहमंत्री रहे हैं, मुझे मालूम है कि उस समय क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि 'I am proud of my brave officers of Punjab Police', जो अपने जीवन को होकर करके देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वह हिम्मत नहीं है। मुझे मालूम है कि चार सौ लोग जतपंस बिम कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऑफिसर गलत काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। They must be tried. अगर ह्यूमन राइट वॉयलेशन का कोई गलत केस है, तो कार्यवाही होनी चाहिए। अभी कश्मीर में रेप का एक मामला आया है, इस पर जरूर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बार-बार यह मैसेज देंगे कि सख्त कार्रवाई करोगे तो फंसोगे, इसलिए शांत रहो, तो यह दुर्भाग्य की स्थिति है। आज हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यह मैसेज देने की कोशिश की है कि एक हाथ पीछे बांधकर लड़ो। यह समस्या है, इसको ठीक करने की जरूरत है। यह बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी स्टेट में, एनकाउंटर में कुछ गलत हुआ है, तो ठीक है, उसकी कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन देश में 2000 एनकाउंटर होते हैं, एक स्टेट में उन्नसी एनकाउंटर होते हैं। वहां आतंकवाद के खिलाफ अच्छी कार्यवाही हुई? मैं गुजरात की बात बोल रहा हूँ। ट्रायल चलता रहे, फंसता रहे, फंसता रहे। मैं यहां किसी गलत को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गृहमंत्री जी बड़ा सवाल यह है कि हम क्या मोराल देने की कोशिश कर रहे हैं? आप देश के गृहमंत्री हैं, मैं आज आपका अभिनंदन करना चाहूंगा जब पहले सवाल में मैंने एसपीओ के बारे में आपसे सवाल पूछा था, and your answer reflected a great degree of concern,

maturity consistent with your office as the Home Minister. What troubles me is, why is it that this kind of approach of consensus is missing when you are talking about terrorism? ये बड़े सवाल हैं। हमें यह सवाल समझना पड़ेगा। आज हमें इस बात की बहुत चिंता हो रही है। 26/11 के बाद माननीय चिदंबरम जी इसी हाउस में आए थे। उन्होंने बहुत आशा जगाई थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि एक जबर्दस्त काउंटर टेरेरिज्म मशीनरी बनेगी। मैं अभी उसकी बात जरूर बताना चाहता हूँ। कहा गया था कि National Counter Terrorism Centre will be set up by 2010. It is not even limping. National Intelligence Grid has been notified, yet even to move. National Technical Research Organization को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया monitoring agency for intelligence purposes. क्या मतलब है? काम नहीं कर रहे हैं। आज मुम्बई के 26/11 हमले के बाद माननीय गृह मंत्री जी, तीन साल होने को आ रहे हैं और आपने यह जो वादा किया था कि देश की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस पर कोई भी प्रामाणिक और प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? यह सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि क्यों नहीं हुई है? यह जनतावार क्यों होती है? मैंने देखा कि जब एनआईए के लोग मुम्बई गए, तो SIT ने मिलने से इंकार कर दिया कि हम काम करना चाहते हैं। Why this turf war cannot be controlled? That is very important. Is the security of India important or the ego battle of various security agencies are important? ये बहुत बड़े सवाल हैं। आज हम आपसे इन सवालों का जवाब सुनना चाहेंगे। हम एक बात और कहना चाहेंगे और मैं यह बात आपकी टिप्पणी से शुरू करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि हमारे पड़ोसी का जो क्षेत्र है, वह बहुत तनाव और आतंकवाद से प्रभावित है। It is vulnerable, if I can quote his exact words. पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या नीति है? माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपकी साफगोई की प्रशंसा करना चाहूंगा कि जब आप कहते हैं कि "ISI has a design to destabilize India", मुझे खुशी होती है कि आप खुलकर बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? जब बातचीत होती है, तो पूरी विदेश नीति में और गृह मंत्रालय की नीति में तरीके से कोई मामला नहीं बनता है। मैंने कांग्रेस के एक महामंत्री की चर्चा की।

ऐसा क्या है कि जब भी आप आतंकवाद के बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ लिखते हैं, तो सबसे पहले वे टिप्पणी करने को तैयार हो जाते

हैं और बड़े अच्छे-अच्छे शब्दों में आपका वंदन करते हैं। हमने उनके कई interviews पढ़े हैं। आप क्या Message दे रहे हैं? Mr. Home Minister, with great respect to you, India and your Government has to recognize that policy with Pakistan and counter-terrorism strategy cannot be segregated or separated. They have to go hand in hand. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुशर्रफ साहब के साथ एक समझौता किया था, जब आगरा पिस कर गया, वे पहली बार अपनी गलती माने, 4 जनवरी, 2004, जब पाकिस्तान ने कहा था कि हम अपनी धरती से किसी आतंकवादी घटना को हिन्दुस्तान के खिलाफ नहीं होने देंगे। आप तो भूल गए थे, क्योंकि आपको एनडीए का कोई काम अच्छा नहीं लगता, आज आपको उसकी याद आती है। 26/11 के बाद आपने उनका कितने dossiers दिए? किस dossier पर काम हुआ? Correct me if I am wrong. अब तक 5 जज बदल चुके हैं, 4 prosecutors बदल चुके हैं। 100 गवाह हैं, अब तक सिर्फ एक गवाह गुजरा है।

This is the level of trial in one of the worst instances of terrorist violence in India from across the border of India. इससे देश का क्या भला होने वाला है? यह सवाल तो कभी उठाना पड़ेगा। यह बहुत गम्भीर सवाल है।

अभी आपने देखा होगा कि डेविड कोलमैन हेडली की गवाही आई थी। आपने कहा था कि वह आपको भी मिलेगा। आपके कुछ लोग वहां उससे बातचीत करने लिए गए थे। ISI का रोल expose हो रहा था, आपको मालूम है। तवफुर राणा को जिस तरह डेनमार्क के केस में तो convict किया गया है और बाकी केस से उसे बरी कदिया गया है, वह भी किस डील के अंतर्गत है, आप भी जानते हैं। लेकिन हम आज आपसे यह जरूर जानना चाहते हैं कि हमारी strategy क्या है? मुम्बई में रब्बी हाउस पर जो हमला हुआ था, उसके खिलाफ लोगों ने एक suit file किया हुआ है, in which they have named ISI as a defendant. Are you willing to organize the Indian community and the victims of terrorist violence from across the border to join in defending that case? What is the role of the Government of India?

माननीय गृह मंत्री जी, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि हम क्या message देना चाहते हैं?

आज मैं पोटा का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि इसमें यह एक

indication है। पोटा को सुप्रीम कोर्ट ने approve किया था, दोनों हाउस ने पास किया था। Campaign हुआ कि पोटा का abuse हो सकता है, इसलिए उसको हटा देना चाहिए। आपने हटा दिया। अब आप पावर में हैं। अगर आपके manifesto esa commitment है, तो आपको हटाना है। आपके उस अधिकार का हम सम्मान करते हैं। लेकिन आपने इसे हटा कर क्या मैसेज दिया आतंकवादियों और उनके आकाओं को, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, चाहे स्मज हो, चाहे हुजी हो, चाहे जो भी हो। और यह तर्क! माननीय गृहमंत्री जी, मैं फिर कहूंगा, आप देश के बहुत बड़े वकील भी हैं, मैं उम्मीद करूँ कि आपकी वकालत बहुत जल्दी शुरू हो जाए, यह हमारी शुभकामना है। Can the possibility and apprehension of abuse become the reason for annulling a law? Indian Penal Code is on the Statute Book for more than 160-70 years. इसका abuse तो होता है। दिल्ली में आपके SHO एक पड़ोसी को झूठा फंसा देते हैं, जिसने उनकी कुछ सेवा नहीं की। बड़े-बड़े केस में फंसा देते हैं। क्या इसलिए हम Indian Penal Code दks annul कर दें। 1988 से इन्कम टैक्स लॉ है, जो 1961 में नया लॉ बना। इंकम टैक्स के आईटीओ, इंकम टैक्स के इंस्पेक्टर लोगों को झूठा फंसाते हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। क्या इसके लिए हम इनकम टैक्स लॉ को annul कर दें। इंस्पेक्टर के false implication पर हम इनकम टैक्स लॉ को नहीं annul करते, एक एसएचओ के false implication पर हम Indian Penal Code को नहीं annul करते, लेकिन आतंकवादियों के प्रचार में हम आतंकवाद के खिलाफ एक instrument पोटा को annul करते हैं। इससे हम क्या संदेश देना चाहते हैं? यह सवाल तो कभी-न-कभी उठाना पड़ेगा। क्यों नहीं उठाना चाहिए? यह इसलिए जरूरी है कि जो प्रश्न आज है कि क्यों हमले होते हैं, तो हमले इसलिए होते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। चर्चा हुई है। ठीक है, माओवाद एक चिंता की बात है। जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो परेशानी है, जो आदिवासियों के अधिकार हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि माओवादियों का एक लक्ष्य है to capture political power over India to the barrel of gun, वायलेंस मीन्स से कैप्चर करो।

आज सुबह प्रश्न काल में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि वे आपकी पार्टी के लोगों को मारते हैं, हामरी पार्टी के लोगों को मारते हैं, पत्रकारों को मारते हैं, पुलिस को मारते हैं, सबको मारते हैं।

मगर माओवादी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बंगाल में मारते हैं, वामपंथियों को मारते हैं, तो वे देश को तोड़ना चाहते हैं। इसकी चिंता होनी चाहिए, गरीबों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। सरकार को आदिवासियों के लिए अच्छा काम करना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, लेकिन जिनका गोल ही दूसरा है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी? आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, यह बहुत गंभीर है। मेरे पास उस जजमेंट की कॉपी है, मैंने उसके ऊपर एक लेख भी लिखा है। I am amazed.

उपसभापति जी, मैं दो लाइनें पढ़ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या लिखा है, यह रिकॉर्ड पर जाना चाहिए, "The problem rests in the amoral political economy that the state endorses and the resultant revolutionary politics that it necessarily spawns." "Tax breaks for the rich and guns for the youngsters....." "The policy of privatisation has also meant that the state has incapacitated itself, actually and ideologically, from devoting adequate financial resources in building the capacity....."

इसका मतलब क्या है? माओवाद की हिंसा को समर्थन करने का एक रास्ता है। हां, मि. राजा, आप और हम बोल सकते हैं, लेकिन I am on a larger issue. अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी जजमेंट में बोलते हैं कि इसी पैमाने पर चलूंगा तो वे पूर्व के जजमेंट को इग्नोर करते हैं, जिसमें कहा हुआ है कि पॉलिसी फॉर्मूलेट करना सरकार का काम है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, आप इसकी चिंता कीजिए।

माननीय गृहमंत्री जी, ये बार-बार संघ का नाम क्यों आता है? संघ का नाम आना ही क्यों चाहिए? वह एक राष्ट्रवादी संगठन है और हमें उस पर गर्व है। हमने खुल कर कहा है, स्वयं संघ के लोगों ने कहा है, यहां तक कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि आतंकवाद कहीं से भी हो, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। गलती किसी ने भी की हो, कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। मुझे एक पीड़ा जरूर हुई और आज मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ, क्या हमने आपके बारे में कोई टिप्पणी की थी या हमारी पार्टी ने कोई टिप्पणी की थी? हम आगे भी टिप्पणी नहीं करेंगे। करप्शन के कुछ मामले हैं, जिन पर अलग से चर्चा होगी तो टिप्पणी करेंगे। हमारे पास आपके बारे में, आपकी सरकार के बारे में कहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन जिस समय आपने यह कहा कि मेरे खिलाफ भाजपा के लोग इसलिए आवाज उठा

रहे हैं क्योंकि मैं right-wing terrorist matter को pursue कर रहा हूँ, यह वक्तव्य कितना जिम्मेवार भरा था?

हम आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं और करते रहेंगे। हमारे लिए लोकतंत्र का वजूद है, लेकिन आतंकवादियों को पाकिस्तान में क्या संदेश गया? आगे से जब हिन्दुस्तान के लोग हम पर आरोप लगाएं, तो जवाब दो, हम नहीं, right-wing terror.

आज मुझे एक बात ध्यान आ गई। जिस दिन 26/11 का इंसिडेंट हुआ था, हम लोग रात भर टीवी देख रहे थे। दूसरे दिन मैंने डेढ़ घंटा पाकिस्तान के टीवी को देखा, उसमें अजमल कसाब के बारे में बताया जा रहा था कि he is a Hindu terrorist, क्योंकि उसके हाथ में saffron बंधा हुआ था। आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्या कहता है।

माननीय गृहमंत्री जी, आतंकवाद एक नासूर है और हमें उससे लड़ना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम अपने राजनीतिक घात-प्रतिघात के भाव में देश की सुरक्षा के भाव को कमजोर नहीं करें। आज यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगा। हमारा देश जब तक आतंकवादियों को यह संदेश नहीं देगा कि अगर तुम कोई कार्यवाही करोगे, तो तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी। एक प्रभावी नेतृत्व, जिसमें आप होंगे, आपके प्रधान मंत्री जी होंगे, आपकी मंत्री परिषद होगी और अगर देश की अपेक्षा होगी तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब तक आप यह प्रभावी संदेश नहीं देंगे कि अगर कोई आतंकवादी आंख उठा कर देखने की कोशिश करेगा तो हम उसकी इन नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे चूर-चूर करेंगे। यह संदेश देने की जरूरत है।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यह संदेश देने में हम असफल होते जाते हैं, जिसका कुछ संकेत आज की बहस में मिला। आप उसको रोकिए। जब आप उसको रोकेंगे, तो ये हमले बंद होंगे और अगर नहीं रोकेंगे, तो हमले बढ़ते रहेंगे। उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

